साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 04 में...
अनिल अग्रवाल और नवीन जिंदल चोर-चोर मौसेरे भाई

पेज 09 में...
सशक्त महिलाओं से बनता है मजबूत राज्य: राजवाड़े

वर्ष : 02 अंक : 07 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 12 साहब! डेथ व्हीकल से तो टैक्स छोड़ देते...

नाना आज़ादी के लिए लड़े अब नातिन अपने हक़ के लिए 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी

गोरे नहीं काले अंग्रेज खतरा...

- प्रथम श्रेणी सूचि में दर्ज स्वर्गीय पंडित बी.जगन्नाथ राय बहादुर मित्तल परिवार सड़क पर
- महिला आरक्षण बिल और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के हिमायती नेता-मंत्री मौन
- घर-दुकान पर आग लगाई गई, भाई पर प्राणघातक हमला हुआ अब जमीन दबाने वालों का खौफ
- जमीन मामले में कोर्ट से स्टे मिला, तहसील दस्तावेज में नाम है दर्ज पर तहसीलदार नहीं मानता
- फ्रीडम फाइटर के परिजनों की मदद के लिए सामने आये एकमात्र नेता पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

राजधानी रायपुर में नेता सत्ता हासिल कर खुश हैं, अफसर बेलगाम हैं, पुलिस नज़राने-जबराने में व्यस्त है और भूमाफिया कब्जा करके कमाई करने में लगे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिससे आम लोग जूझ रहे हैं। देश को गोरे अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद करवाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की नातिन आज के काले अंग्रेजों से अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। दुबली-पतली, अस्थमा पीड़ित एक महिला कामिनी मित्तल पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है। रायपुर के मोतीबाग उद्यान के पास बैठी कामिनी की दो मांग भी सरकार और सरकारी अफसरों के कान में नहीं पहुंची है। गर्व से कामिनी बताती है उनके नाना देश की आज़ादी में जेल गए, अंग्रेजों की लाठियां खाये और उनके नाम से आधा दर्जन ट्रस्ट भी संचालित हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम श्रेणी सूचि में दर्ज स्वर्गीय पंडित बी.जगन्नाथ राय बहादुर मित्तल की नातिन हैं कामिनी मित्तल। कामिनी अपने हक़ की जमीन, दोषी तहसीलदार पर कार्रवाई, उसके घर को आग लगाने वालों और भाई मिमोह पर प्राण घातक हमला करने वालों पर कार्रवाई चाहती है।

शहर सत्ता/रायपुर। महतारी वंदन, महिला आरक्षण बिल और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के हितैषियों के राज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की नातिन का परिवार आज सड़क पर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार पर पहले प्राणघातक हमला किया गया। फिर उनको उनकी ही जमीन से खदेड़ने के लिए घर पर आग लगा दी गई।

इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो षड्यंत्र पूर्वक उसके हक़ की जमीन पर कब्जा करके बेदखल कर दिया गया। इस कुत्सित कार्य में एक पार्षद और पूर्व महापौर समेत कथित भूमाफियाओं पर आरोप है। इनके इशारे पर नगर निगम ने नल कनेक्शन भी काट दिया है। यह सब दुर्व्यवहार उस परिवार के साथ राजधानी रायपुर में हो रहा है जिनके नाना गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मुखर हो कर देश की आज़ादी के लिए लड़े और प्रथम श्रेणी के स्वतंत्रता सग्राम सेनानी की सूचि में दर्ज हैं, उसी परिवार के सदस्य आज अपने हक़ के लिए काले अंग्रेजों से जूझ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित बी.जगन्नाथ राय बहादुर की नातिन कामिनी मित्तल, उनका नाती मिमोह मित्तल अपने साथ हुई हिंसा, दुर्व्यवहार और एक तहसीलदार द्वारा जानबूझकर की जा रही गैर वाजिब हरकत से त्रस्त होकर भूख हड़ताल में बैठे हैं।

पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर करते हैं मदद

दुखों का पहाड़, तहसीलदार, पुलिस का दुर्व्यवहार और अपने हक़ की जमीन के लिए अंतहीन लड़ाई की चिंता कामिनी की पेशानी में दिखती है और रसूखदार भूमाफियाओं, उसकी जमीन पर कब्जा करके कारोबार करने वाले गुंडों का खौफ भी उसकी आंखों में है। उसकी मदद के लिए कोई एनजीओ, कांग्रेस, कोई भाजपा नेता या अफसर अब तक नहीं आये। पूर्व गृहमंत्री और विधायक ननकी राम कंवर ही स्वतंत्रता सेनानी की नाती को आर्थिक ही नहीं सैद्धांतिक समर्थन भी करते हैं। कामिनी का कहना है अब तक हर कठिनाइयों में पिता जैसा साथ, समर्थन और सहयोग ननकी बाबू जी से मिला है। रोजी रोटी छिन गई थी तो ननकीराम जी ही एकमात्र नेता है, जिन्होंने परिवार को आर्थिक मदद किये। भूख हड़ताल पर भी वो मेरे साथ बैठ रहे थे लेकिन मैं उन्हें स्वस्थ्य और दीर्घायु रहें यही चाहती हूं। क्योंकि हम जैसों का एकमात्र सहारा वही है।

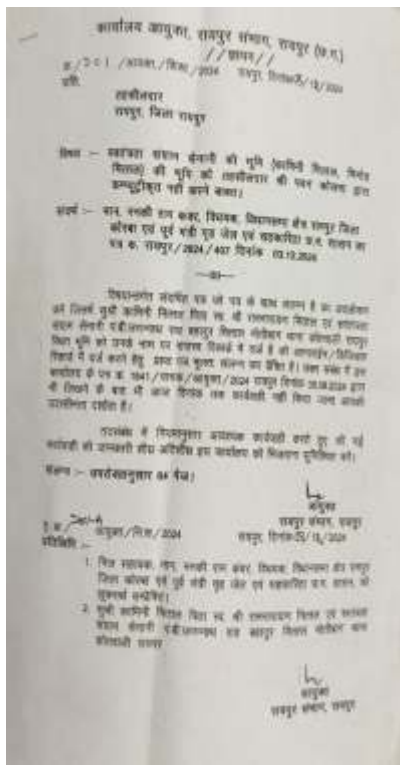

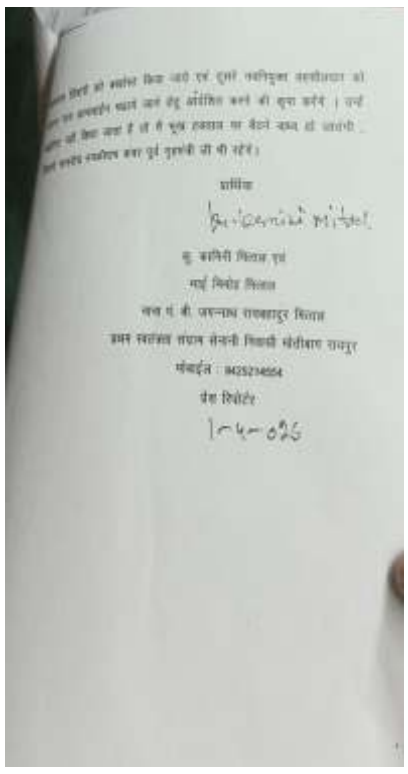

घर में लगाई आग, सब जलकर हो गया ख़ाक

6 दिनों से तेज गर्मी में भूखी बैठी कामिनी ने रुंधे गले से बताया कि 23 अप्रैल 2017 को पौने 3 बजे रात को घर दुकान में आग लगा दिए। कोतवाली थाना में घटना की जानकारी और आरोपियों की नामजद रिपोर्ट भी की लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इस हादसे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाणपत्र समेत कोर्ट-कचहरी के लिए रखा पैसा और समान स्वाहा हो गया। परिवार में 5 लोगों की जिम्मेदारी कामिनी पर ही है इसके लिए वह सत्यज्ञान समागम प्रिंट मीडिया में कार्यरत है।

अपनी नहीं भाई के जान की है चिंता

कामिनी अस्वस्थ भी हैं और बेहद कमजोर भी, लेकिन उनका कहना है कि वे अपने हक़ और परिवार का एकमात्र आर्थिक सहारा इस जमीन को आखरी दम तक लेने के लिए लड़ती रहूंगी। भूख हड़ताल पर बैठी कामिनी ने शहर सत्ता को बताया कि कोर्ट से स्टे, तात्कालीन कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे तथा संभागायुक्त एमडी कावरे तक ने उनके हक़ की जमीन को भू-अभिलेख में चढ़ाने का निर्देश दिया। तहसील दस्तावेज में यह दर्ज भी है लेकिन उसे ऑनलाइन कम्प्यूटर में दर्ज नहीं करवाने के लिए शहर के चंद नेता, पूर्व पार्षद-महापौर और तहसीलदार रोककर रखे हैं। छोटे भाई और स्थायी विकलांग कर दिए गए मिमोह की सुरक्षा की चिंता भी कामिनी को सताती है।

भाई को मारकर फेंक दिए थे रेल पटरी पर

कामिनी ने बताया कि उसके छोटे भाई मिमोह मित्तल (30 साल) को मकान और दुकान समेत जमीन के लिए मुझपर दबाव बनाने 25 अगस्त 2019 को जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला पूर्व पार्षद और महापौर समेत अन्य आधा दर्जन लोगों ने करवाया था। सरोना रेल पटरी में मारकर फेंक दिया गया था। लेकिन मिमोह को ट्रेन आने से पहले ही लोगों ने देख लिया और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर घायल मिमोह कोमा में थे और जान बची लेकिन वे अब स्थायी विकलांग हो गए हैं।

इन लोगों के नाम से चिढ़ जाती है कामिनी

स्वास्थ्यगत कारणों से जब कामिनी इलाज के लिए मुंबई गई थी तब जमीन दलाल, भूमाफियाओं और अपराधियों ने कब्जा कर लिया। मुस्लिम सामुदायिक भवन मोतीबाग हॉल भी उसके हक़ की जमीन में बना है। दुकानों का निर्माण, मोतीबाग के सामने कथित तौर पर सालों साल चली चौपाटी के लिए कामिनी को कुछ लोगों ने खासा दुख दिया। कामिनी किसी मख्मूर, अच्छू उर्फ़ असलम समेत पूर्व महापौर एजाज ढेबर का नाम लेकर अब भी कोसती है। भूख हड़ताल और धरने पर बैठी कामिनी ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी देर रात आये और मुझपर तंज कसे बोले; 'ननकी राम भूख हड़ताल में नहीं बैठे क्या' ? बेजा मांग का भी आरोप कामिनी ने लगाया है। तहसीलदार राममूर्ति दीवान के संबंध में कहा वो बोलते हैं नाम ऑनलाइन नहीं चढाने के लिए शासन के मंत्री का निर्देश है

महापौर एजाज ढेबर और स्वतंत्रता सेनानी के अरबो की जमीन का कनेक्शन, एजाज ढेबर समेत कईयों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर

पूर्व सीबीआई जज प्रभाकर ग्वाल से पीड़िता कामनी मित्तल ने जमीन से जुड़ी कड़ियों को किया साफ

भूख हड़ताल का छठवां दिन, हालत ख़राब

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित बी.जगन्नाथ राय बहादुर मित्तल की नातिन कामिनी को आज भूख हड़ताल में बैठे छठवां दिन है। उनका भाई मिमोह का कहना है कि दीदी उसे भूख हड़ताल में इसलिए नहीं बैठने दी क्योंकि आगे का संघर्ष मुझे करना है। दीदी की मांग है कि तहसीलदार राममूर्ति दीवान के खिलाफ टीएल जारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है और हक़ की जमीन अब तक ऑनलाइन कम्प्यूटर में दर्ज नहीं की गई है। जब तक यह दो मांग पूरी नहीं होगी वो धरना और भूख हड़ताल करती रहेंगी। कामिनी को श्वांस की बीमारी भी है और हालत ख़राब है। मोतीबाग सामुदायिक भवन के सामने सड़क किनारे वह बैठी हुई है।

कोयला घोटाला में आरोप के बाद बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई

आईएएस समीर की 30 एकड़ बेनामी संपत्ति कुर्क

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश में हुए 540 करोड़ के अवैध कोल लेवी केस में ईओडब्ल्यू ने शनिवार को निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई की महासमुंद के बागबाहरा स्थित 9 प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। इनमें एक भी प्रॉपर्टी समीर के नाम पर नहीं है। ये संपत्तियां उनके रिश्तेदारों और अलग-अलग फर्मों के नाम पर खरीदी गई हैं।

कुल मिलाकर करीब 30 एकड़ जमीन पर कार्रवाई हुई है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 करोड़ रुपए की पांच प्रॉपर्टी कुर्क की थी और इनके खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी थी।कुछ माह पहले ईओडब्ल्यू ने निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपए की 16 प्रॉपर्टी कुर्क की थी। वहीं, ईडी ने 39 करोड़ रुपए की 29 प्रॉपर्टी कुर्क की है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि कोयले से मिले कमीशन से ये संपत्तियां खरीदी गई हैं। समीर ने अधिकांश निवेश अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर किया है। इन संपत्तियों को कम कीमत पर खरीदा गया, जबकि इनकी वास्तविक कीमत कहीं अधिक है। 4 किलो सोना और 24 कैरेट का हीरा जब्त: ईडी ने अक्टूबर 2022 में समीर के घर पर छापा मारा था। तलाशी के दौरान उनकी पत्नी के पास से 4 किलो सोना, 24 कैरेट का एक हीरा और 47 लाख रुपए नकद मिले थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया था। इसके बाद 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई थी। अब ईओडब्ल्यू ने आगे की कार्रवाई करते हुए नई कुर्की की है। 250 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क: अवैध कोल लेवी केस में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, सुनील अग्रवाल समेत 20 से अधिक लोगों की 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है। इसमें जमीन, मकान, फ्लैट समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। अधिकांश आरोपियों ने संपत्तियां अपने नाम पर न लेकर परिचितों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी हैं। क्या है कोल लेवी केस| जांच एजेंसियों के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान कोल परिवहन पर अवैध टैक्स वसूला जाता था। एक गाड़ी से प्रति टन 25 रुपए की वसूली की जाती थी। यह रकम सिंडिकेट के माध्यम से नीचे से ऊपर तक पहुंचती थी। आरोप है कि यह पैसा मंत्री, विधायक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया गया। इस मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों एजेंसियों की जांच जारी है और अंतिम चार्जशीट पेश नहीं किया गया है।

समीर की जब्त संपत्ति का विवरण

महासमुंद बागबाहरा, बिहाझर में 30 एकड़ जमीन

जमीन मालिक	खरीदी वर्ष	क्षेत्रफल
प्रेम अग्रवाल	2022	0.20 एकड़
प्रेम/उमा अग्रवाल	2022	0.99 एकड़
प्रीति गोदारा (तिरुमाला एग्रो)	2022	3.58 एकड़
प्रीति गोदारा (फर्म/कंपनी)	2022	7.12 एकड़
प्रीति गोदारा (फर्म)	2022	7.54 एकड़
सुरेश अग्रवाल	2022	4.94 एकड़
संकल्प अग्रवाल	2022	5.36 एकड़

{एक भी प्रॉपर्टी समीर बिश्नोई के नाम पर नहीं है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 151 लोगों पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई

- **पुलिस की सरप्राइज चेकिंग में फंसे, अफसरों ने 9 प्वाइंट में जांच कर पकड़ा**

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। 18 अप्रैल 2026 की रात शहर में चलाए गए सरप्राइज अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 151 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई महज 2 घंटे के भीतर शहर के 9 अलग-अलग स्थानों पर की गई। इस अभियान का नेतृत्व यातायात और प्रोटोकॉल उपायुक्त विकास कुमार ने किया। पुलिस की टीमों ने रात 11 बजे से 1 बजे तक अलग-अलग चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच की। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए चालकों की जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए।

2456 शराबी वाहन चालकों को पकड़ चुकी पुलिस

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, साल 2026 में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अब तक 2456 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है, जिससे साफ है कि पुलिस इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान बचाना है।

डीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का 117वां दिन:परशुराम जयंती पर रामायण पाठ

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन शनिवार को 117वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने पूरे जोश और दृढ़ संकल्प के साथ आंदोलन जारी रखते हुए परशुराम जयंती के अवसर पर रामायण पाठ का आयोजन किया। अभ्यर्थियों ने भगवान परशुराम के आदर्शों को स्मरण करते हुए यह आयोजन किया। उनका कहना है कि यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सरकार को जगाने और उसकी संवेदनशीलता को झकझोरने का एक शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक प्रयास है।

शिक्षा मंत्री के बंगले की ओर निकाली रैली

रामायण पाठ के बाद अभ्यर्थियों ने भगवा ध्वज के साथ शिक्षा मंत्री के बंगले की ओर रैली निकाली, ताकि अपनी मांग सीधे सरकार तक पहुंचा सकें। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को तूता धरना स्थल के गेट पर ही रोक दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार संवाद से बच रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

2300 पदों से आगे बढ़ा आंदोलन, बना अधिकार की लड़ाई

अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका संघर्ष अब केवल 2300 पदों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन चुका है। 117 दिनों से जारी यह आंदोलन अब जन-जन की आवाज बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रदेश की जनता, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस आंदोलन का समर्थन करें और इसे जनांदोलन का रूप दें।

राजनांदगांव में 45°C पहुंचा पारा, और तपेगा मौसम, रायपुर में सामान्य से 5°C ज्यादा तापमान

छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट, पसीने से लथपथ हुए लोग

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। शनिवार को राजनांदगांव जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के इलाकों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बेहद जरूरी काम न हो तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें। अगर बाहर जाना अनिवार्य हो, तो स्कार्फ का उपयोग करें।

रायपुर में सामान्य से कहीं ज्यादा गर्मी

राजधानी रायपुर में इस समय तापमान औसत से काफी ऊपर चल रहा है। अप्रैल महीने का सामान्य अधिकतम तापमान जहां करीब 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं अभी पारा 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी शहर में सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यही वजह है कि दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं और लोगों को लगातार असहजता महसूस हो रही है।

रायपुर के पुराने आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में तापमान खतरनाक स्तर तक जा सकता है। शहर का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 30 अप्रैल 1942 को 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 1980 के बाद 28 अप्रैल 1999 को 45.4 डिग्री दर्ज हुआ था। हाल के वर्षों में भी तापमान बार-बार 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी पारा 45 डिग्री के करीब जा सकता है।

अप्रैल का आखिरी हफ्ता क्यों सबसे खतरनाक होता है

मौसम के लंबे रिकॉर्ड यह बताते हैं कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी अपने चरम पर होती है। 25 से 30 अप्रैल के बीच ही ज्यादातर बार सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अभी मौसम इसी दौर में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आने वाले कुछ दिन और ज्यादा गर्म रहने की संभावना है।

क्यों बन रही है हीट वेव की स्थिति

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी कम है और सतही दबाव भी गिर रहा है। इन परिस्थितियों में तेज धूप और गर्म हवाएं मिलकर हीट वेव की स्थिति बनाती हैं। यही कारण है कि दिन के साथ रात में भी गर्मी बनी रहती है।

भूपेश बोले-अनिल अग्रवाल और नवीन जिंदल चोर-चोर मौसेरे भाई

सरकार भी साथ खड़ी है, महिला आरक्षण बिल पर कहा- इनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं

शहर सत्ता/रायपुर/दुर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। पूर्व सीएम ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। भूपेश बघेल ने सक्ती प्लांट हादसे को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में नवीन जिंदल खड़े हो गए हैं। पूर्व सीएम ने अनिल अग्रवाल और नवीन जिंदल को चोर-चोर मौसेरे भाई बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोठानों में शराब बेची जा रही है, गांजा की तस्करी हो रही है और अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

खेल कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व सीएम

दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल रविवार को भिलाई के सेक्टर-6 में आयोजित खेल कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र-राज्य और भाजपा पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, जब बिल पहले ही पास हो गया था, तो ढाई साल तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करने का क्या मतलब है, जब तक इसे जमीन पर लागू नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जनगणना और परिसीमन का बहाना बना रही है। अगर सरकार चाहे तो पहले जनगणना और जाति जनगणना करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जनगणना के परिसीमन करने से SC, ST और OBC वर्गों को नुकसान होगा और छोटे राज्यों पर भी असर पड़ेगा।

महिलाएं शुरू से समझदार, जानती हैं किसकी नियत क्या है

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीजेपी ने इस बिल को अपने स्वार्थ के लिए लाया है, लेकिन देश की महिलाएं मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं शुरू से समझदार रही हैं और जानती हैं कि किसकी नियत क्या है। उन्होंने कहा कि 2023 में बिल पास होने के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया, जब एक बिल पहले से पारित है, तो दूसरे को लाने की क्या आवश्यकता है? वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं और उसमें राजनीतिक दलों पर टिप्पणी कर रहे हैं।

चुनाव के बाद तेजी से बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

पूर्व सीएम ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें चुनाव के चलते फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इनके दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उनके अनुसार यह स्थिति 29 अप्रैल तक बनी रह सकती है, क्योंकि चुनाव जारी हैं, लेकिन चुनाव के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका है।

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने कहा कि आज गोठानों में शराब बेची जा रही है, गांजा की तस्करी हो रही है और अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनमें ED को जांच करनी चाहिए, लेकिन एजेंसी अब तक सक्रिय नहीं दिख रही।

उद्योगपति नवीन जिंदल बोले- अनिल अग्रवाल पर FIR से पहले जांच हो

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में कुल 24 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में कुल 36 मजूदर झूलसे थे। 12 घायलों का इलाज अभी जारी है। घटना की शुरूआती जांच में लापरवाही सामने आने के बाद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में FIR दर्ज हुई है। इस कार्रवाई पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि जांच से पहले अनिल अग्रवाल का नाम FIR में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय है। पहले घटना की जांच होनी चाहिए। 14 अप्रैल को हुए हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने 15 अप्रैल को घटना स्थल की जांच की। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को सौंपी गई शुरूआती जांच रिपोर्ट में प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। जिसके बाद FIR की कार्रवाई की गई। उद्योगपति नवीन जिंदल ने अनिल अग्रवाल पर FIR होने पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहले घटना की जांच होनी चाहिए और सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जब सरकारी कंपनियों या रेलवे में घटनाएं होती हैं, तो क्या हम चेयरमैन का नाम लेते हैं? नहीं। यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने घटना पर दुख जताया। सिंघीतराई प्रोजेक्ट में NGSL की टीम तैनात है, जिसमें प्रोजेक्ट हेड और साइट इंचार्ज के रूप में राजेश सक्सेना कार्यरत हैं। वे वरिष्ठ महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं। वेदांता प्रबंधन और NGSL कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच समन्वय की मुख्य कड़ी माने जाते हैं। यूनिट-1 के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। इसके अलावा मेंटेनेंस टीम बॉयलर, टरबाइन और अन्य सहायक उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे में ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े सभी अधिकारियों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने वाली युवती अरेस्ट

शहर सत्ता/रायपुर। सोशल मीडिया पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में आक्रोश का माहौल है। रविवार को राजधानी में भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, भिलाई में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलग-अलग संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भिलाई नगर थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए युवती के खिलाफ एक्शन की मांग की। इसके अलावा राजनांदगांव में भी लोगों ने थाने का घेराव किया। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है।

- **रायपुर-भिलाई और राजनांदगांव में नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव**

जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, भिलाई के वैशाली नगर की रहने वाली अनामिका उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी है। रविवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग भिलाई नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं भी थाने के अंदर पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि युवती लगातार सोशल मीडिया पर एक समाज को टारगेट कर वीडियो बना रही है, उसने बाबा साहेब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है।

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर होगी ड्रोन से निगरानी

- **3D मैपिंग से पकड़ेंगे ओवर-माइनिंग, 10 रूट्स पर ई-चेक गेट**

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए अब हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला लिया है। एरियल सर्वे और 3D मैपिंग के जरिए खदानों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जिससे ओवर माइनिंग और लीज एरिया से बाहर खनन जैसी गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। खनिज विभाग के मुताबिक, शुरुआती चरण में 5 ड्रोन कैमरे तैनात किए जाएंगे। इन्हें सर्विस मोड पर लिया जाएगा और संचालन के लिए विशेषज्ञ टीम भी मौजूद रहेगी। इन ड्रोन को रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर जैसे जिलों में लगाया जाएगा, जहां अवैध खनन की शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं। 10 रूट्स पर ई-चेक गेट सिस्टम लगेगा। खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि, जल्द ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से होगी निगरानी

ड्रोन के जरिए दुर्गम जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से निगरानी हो सकेगी, जहां पारंपरिक निरीक्षण मुश्किल और समय लेने वाला होता है। ड्रोन से मिलने वाली हाई-रिजोल्यूशन तस्वीरें और मैपिंग डेटा सीधे विभाग तक पहुंचेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि, खनन तय लीज क्षेत्र के भीतर हो रहा है या बाहर। समय-समय पर डेटा की तुलना कर ओवर माइनिंग की पहचान की जा सकेगी और तुरंत कार्रवाई संभव होगी। खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार 10 प्रमुख रूट्स पर ई-चेक गेट सिस्टम लागू कर रही है। इस डिजिटल सिस्टम में खदान से निकलने वाले हर वाहन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। वाहन नंबर, खनिज का प्रकार, मात्रा और गंतव्य जैसी जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी। इससे ओवरलोडिंग, बिना रॉयल्टी परिवहन और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। पहले जहां कागजी दस्तावेजों में हेरफेर की गुंजाइश रहती थी, अब डिजिटल सिस्टम से गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आएगी।

प्राइवेट कॉलोनियों में पानी सप्लाई की होगी जांच

जल संकट के बीच बड़े बिल्डर्स पर नजर

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में बढ़ते जल संकट के बीच नगर निगम ने निजी कॉलोनियों को दी जा रही पानी सप्लाई की व्यवस्था की जांच शुरू करने का फैसला लिया है। खासतौर पर बड़े बिल्डर्स के साथ किए गए एग्रीमेंट की पड़ताल की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं नियमों के विपरीत पानी की आपूर्ति तो नहीं हो रही।

नगर निगम के जोन-5, जोन-3 और आसपास के क्षेत्रों में पानी की सबसे अधिक मांग सामने आई है। इन इलाकों में नियमित सप्लाई प्रभावित होने से लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि जहां टंकियों से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है, वहां टैंकरों के साथ बोरवेल के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिल सके।

इंजीनियरों को दिए सख्त निर्देश

महापौर मीनल चौबे ने जलकार्य विभाग के इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे फिलहाल केवल जलापूर्ति व्यवस्था पर ध्यान दें। अन्य कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाएगा और सभी जोनों में लगातार निगरानी की जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा है कि पानी सप्लाई से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। जहां भी अनियमितता या गड़बड़ी मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

गर्मी के साथ बढ़ रही परेशानी

तापमान बढ़ने के साथ शहर में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ऐसे में निगम ने सख्ती दिखाते हुए प्राइवेट कॉलोनियों को दी जा रही सप्लाई और उनके एग्रीमेंट की जांच करने का फैसला लिया है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

महिला हित की अनदेखी फिर ठंडे बस्ते में आरक्षण

अंततः जिसका अंदेशा था, वही हुआ। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत के अभाव में लोकसभा से पारित नहीं हो सका। इसी के साथ एक तरह से महिला आरक्षण फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। कहना कठिन है कि अब वह कब लागू हो सकेगा। यदि पक्ष-विपक्ष के बीच निकट भविष्य में कोई सहमति नहीं बनती तो आसार यही हैं कि महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनाव के पहले क्रियान्वित नहीं हो सकता।

महिला आरक्षण में और अधिक देरी दुर्भाग्य की ही बात होगी। ध्यान रहे महिला आरक्षण के सपने को साकार करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। महिला आरक्षण का विचार करीब तीन दशक पहले राजनीतिक विमर्श का विषय बना था। इसके बाद सभी दल महिला आरक्षण के पक्ष में बातें तो करते रहे, लेकिन वे उसके लिए मन से तैयार नहीं हुए। इसी कारण महिला आरक्षण संबंधी विधेयक कई बार संसद में पेश होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ सका। अंततः 2023 में वह सभी दलों की सहमति से परित तो हुआ, पर इस प्रविधान के साथ कि उसे 2029 के आम चुनाव में लागू किया जाएगा। इसका कारण 2021 में होने वाली जनगणना में विलंब होना रहा। चूंकि नई जनगणना अब जाकर शुरू हुई है और उसके नतीजे आने में समय लगेगा, इसलिए मोदी सरकार ने अगले आम चुनावों से ही महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने और विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने के लिए यह फार्मूला रखा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके महिला आरक्षण को लागू किया जाए।

पता नहीं क्यों विपक्ष को सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का फार्मूला रास नहीं आया, जबकि इससे किसी भी राज्य और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों के राजनीतिक हितों की कोई क्षति नहीं होने जा रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष नई जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की अपनी जिद का परित्याग करता, क्योंकि यदि जनसंख्या के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाता है तो कम आबादी वाले दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य तो राजनीतिक रूप से नुकसान में ही रहेंगे। जहां तक विपक्ष की यह मांग है कि महिला आरक्षण में विभिन्न वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया जाए तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 2023 में ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पारित न होने से विपक्ष अपनी जीत की घोषणा अवश्य करेगा, लेकिन ऐसा करके वह देश की महिलाओं को मायूस ही करेगा। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को झटका लगा है, लेकिन उसे यह प्रचार करने का अवसर हाथ भी लगा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण लागू नहीं होने दिया और इस तरह आधी आबादी की आशाओं पर तुषारापात किया।

थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है

डॉ. मोनिका शर्मा

इन दिनों संसद के भीतर और बाहर खूब चर्चा बटोरने वाला महिला आरक्षण बिल लोकसभा में मतदान के दौरान पारित नहीं हो पाया। बिल के समर्थन में 298 और असहमति में 230 वोट पड़े। देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए गए इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए सरकार दो तिहाई वोट जुटाने में विफल रही। ध्यातव्य है कि महिला आरक्षण कानून में देश की संसद और राज्य विधान सभाओं में आधी आबादी के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान है। यही वजह है कि सियासी दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले कानून में संशोधन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र की चर्चा में राजनीति से जुड़े लोगों की नहीं, देश के आम परिवारों की भी खासी रुचि थी। बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। बिल पर हुई 21 घंटे की गहन चर्चा में कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे, इनमें 56 महिला सांसद भी थीं। वोटिंग के बाद परिणाम स्त्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाने से जुड़े बिल के पास न होने के रूप में सामने आया। सरकार की ओर से 'नारी शक्ति वंदन' मुहिम के तौर पर जनमानस तक पहुंचाए गए बिल को लेकर समझाया गया कि यह देश की आधी आबादी के सम्मान और अधिकारों को मजबूती देने कदम वाला है।

निराशाजनक रहा नतीजा

सत्ता पक्ष ने बिल को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखने की बात कही। वहीं, विपक्ष ने इस संशोधन में समाहित परिसीमन को लेकर सरकार को घेरा। संविधान संशोधन बिल में प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने एवं परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू किए जाने की योजना थी। कुल मिलाकर सियासी वादों, दावों और आशंकाओं से जुड़ी इस चर्चा का नतीजा देश की महिलाओं के लिए निराशाजनक ही रहा। विचारणीय है कि पर्याप्त समर्थन के अभाव में गिरे इस बिल से राजनीतिक पटल पर देश की आधी आबादी की भागीदारी में बढ़ोतरी का प्रयास एक बार फिर अटक गया है। देश की ऐतिहासिक निर्णय में आया यह अटकाव आमजन को भी हैरान-परेशान करने वाला है। यहां तक कि कई महिला सांसदों और समर्थकों ने भी इस बाबत निराशा और आक्रोश जताया है। इस मायूसी की अहम वजह यह है कि देश के सियासी परिदृश्य में हर स्तर पर ही महिलाओं की भागीदारी आज भी बहुत कम है।

धरातल पर नहीं उतरा आरक्षण

यह बिल 2029 के आम चुनाव से पहले स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना का हिस्सा था। ज्ञात हो कि फिलहाल सदन में 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। बावजूद इसके 2023 में मिला 33 फीसदी आरक्षण का कागजी अधिकार धरातल पर नहीं उतर सका। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा महिला आरक्षण बिल, ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये देश की दिशा और दशा बदलने वाला बिल है। पीएम ने परिसीमन पहले के अनुपात के अनुसार ही किए जाने का विश्वास दिलाते हुए इस बात को खारिज किया कि निर्णय प्रक्रिया किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव करेगी। साथ ही यह भी जोड़ा कि 33 फीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, संतुलन साधने के प्रयासों के बीच हमारे देश के राजनीतिक परिवेश में बड़े बदलाव की आहट को ठेस तो लगी ही है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्त्री जीवन से जुड़े हर पक्ष पर इसका असर होगा। गौरतलब है कि इस बिल के साथ परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी जुड़े थे।

सियासी खेल का खामियाजा

महिला आरक्षण के साथ ही एक विधेयक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए भी आवश्यक था। ऐसे में मुख्य संविधान संशोधन बिल के गिर जाने के कारण सरकार ने इन दोनों विधेयकों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि सरकार ने आगे भी इस बिल को लाने के लिए प्रयासरत रहने की बात कही है। स्पष्ट है कि परिसीमन से जुड़ी सरकार की मंशा हो या विपक्ष का संदेह, महिलाओं को इस सियासी खेल का खामियाजा उठाना होगा। आखिर क्यों और कब तक मतदान के लिए लंबी कतारों में दिखने वाली आधी आबादी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने में पीछे रहे? हालिया वर्षों में शिक्षा और सजगता की बदौलत राजनीतिक सक्रियता के मोर्चे पर स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने की तुलना और सत्ता की बागडोर संभालने के मामले में स्त्रियों के आंकड़े बेहद कम हैं।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

जबकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-पारिवारिक मोर्चे पर बेहतरी से जोड़कर देखने वाला पहलू है। इतना ही नहीं, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्या बल भर नहीं होता। महिलाओं का संसद में पहुंचना स्त्रियों की समस्याओं को मुखर स्वर मिलने जैसा है। इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरने से लेकर जीत हासिल करने तक महिला जनप्रतिनिधियों को भी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आधी आबादी के आगे बढ़ने की राह में पहले से ही कई बाधाएं मौजूद हैं। हमारे देश की आबादी का 48.5 फीसदी हिस्सा महिलाएं हैं। स्त्रियां हमारे सामाजिक-पारिवारिक जीवन की धुरी हैं। आर्थिक मोर्चे पर आज भी आत्मनिर्भर महिलाओं के आंकड़े कम हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और श्रम से जुड़े मुद्दे भी बहुत हद तक उपेक्षित ही हैं। कुल मिलाकर यह समझना मुश्किल नहीं कि भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी राजनीतिक भागीदारी से भी जुड़ी है। ऐसे में महिलाओं के बुनियादी अधिकारों और आमजीवन से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में अनगिनत विरोधाभासी स्थितियों से जूझते हुए भी आगे बढ़ रही महिलाओं के जीवन में आज भी थोड़ा है और ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए गंभीर मंथन की सख्त आवश्यकता है।

सियासी महाकुंभ में समाजवाद

आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री और समाजवादी नीतीश कुमार का पतन सहयोगी बनते साजिशी दोस्तों ने करा ही दिया। तीन दशकों तक नीतीश ने खुद को राज्य बल्कि केंद्र की राजनीति के दिशानिर्देशक की तरह दांव पेंचों के साथ सक्रिय तो रखा था। हासिल यह है कि बिहार में पहले उनके साथ रहे फिर कभी छिटके दूसरे बड़े समाजवादी नेता लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की हालत लचरपचर हो गई है। समाजवादियों का गढ़ बिहार दक्षिणपंथी राजनीति के चंगुल में है। उत्तरप्रदेश में अलबत्ता अभी अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है। इसके अलावा देश में समाजवाद के कुछ नामलेवा छोटे छोटे चिराग हैं। जो अंधेरे से लड़ने की कोशिश में जुगनुओं की तरह राजनीति के जंगल में भटकते गिरते पड़ते दिखाई देते हैं।

दरअसल समाजवाद एक विचार जिसका भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति से बहुत कुछ लेना देना है। कई देश सफल होकर समाजवादी रहे हैं। अब भी कहीं ना कहीं समाजवाद उन देशों की सत्ता की राजनीति में खदबदा रहा है। इस व्यापक और लचीली परिभाषा में साम्यवाद शब्द को भी शामिल कर लेना चाहिए। थोड़े से तरह के हलफे के बावजूद उनका रास्ता एक तरह का है। हालांकि कम्युनिस्टों की चूलें अब ढीली हो गई हैं। कोई देश अब पूंजीपतियों के चंगुल से बाहर नहीं हैं। चाहे रूस और चीनी क्यों न हों। भारत की राजनीति में समाजवाद एक उदार और साफ सुथरा चेहरा लिए दशकों तक अपना भविष्य ढूंढ़ा करता। उम्मीदों के दिए की तरह टिमटिमा रहा था। इतिहास कभी कभी असली जननायकों को अंधेरे में ठेल देने की खलनायकी नहीं छोड़ता। राजनीतिक बियावान में सबसे पहले तो 23 बरस के क्रांतिकारी शहीद भगतसिंह ने देश को नारा दिया था कि हर हाल में भारत में समाजवाद को लाना है। उससे कमतर कोई विकल्प नहीं। कोई समझोता नहीं। देश में निजी उद्योगपतियों को फलने फूलने नहीं देना चाहिए। वरना ये जनता का खून चूसेंगे। उसी इतिहास ने अपने मुंह से कबूला कि भगत सिंह ने भविष्यवाणी की थी उस पर इतिहास को शर्मसार रहना पड़ेगा।

समाजवाद का जब सियासत में एक तरह से उद्गम था। तब भारत की संविधान सभा में संविधान के मकसद पर नेहरू ने अप्रतिम भाषण दिया था। लेकिन उस भाषण में उन्होंने संविधान में शब्द के रूप में 13 दिसंबर 1946 को दुर्भाग्य से समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया। संविधान नियंता बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 को कहा था कि पंडित जी तो एक समाजवादी की हैसियत से मशहूर हैं। लेकिन समाजवाद का उल्लेख नहीं करने से मुझे बड़ी निराशा हुई है। उसके बाद तो एक बाद सी आ गई। विश्वंभर दयाल त्रिपाठी, दामोदर स्वरूप सेठ, काजी सैयद करीमुद्दीन और सबसे बढ़कर के0 टी0 शाह ने हमलावर भाषण दिया कि समाजवाद को क्यों नहीं साफ साफ लिखा जाता। वरना भारत की आजादी का कोई अर्थ नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि समाजवाद शब्द भारत में गरीबी, जाति प्रथा और स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचारों की फेहरिस्त में काफी दिनों से है। जितनी समाजवादी पार्टियां भारत में बनी बिगड़ीं और बार बार बनती और बिगड़ती रहीं। उससे राजनीति के इतिहास से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड का सरोकार रहा है। बिड़ला, टाटा, डालमिया और तमाम उद्योगपति संविधान सभा की कार्यवाही में इस तरह हावी थे कि उनकी उपेक्षा करना संविधान सभा के लिए संभव ही नहीं था। वरना देश में आर्थिक भूचाल आ जाता। एक बेहद गरीब लेकिन उम्मीदों से भरपूर नेहरू सरकार के मुखिया इंग्लैंड के फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे। हेराल्ड लस्की, ओल्डस हक्सले और न जाने कितने विचारक उस वक्त नेहरू के जेहन में दाखिल हो गए थे। जब वे इंग्लैंड में बैरिस्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तब भी नेहरू ने यह कहा था कि समाजवाद लाकर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ेगा। वरना देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस नेहरू और इंग्लैंड ने एक के बाद एक राजाओं की ही थैली और विशेषकर जमींदारी उन्मूलन और कई निजी उद्योगों का खुले आम राष्ट्रीयकरण किया। यह एक कहानी है।

महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम!

महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम- 'हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल) रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने देश की नारी शक्ति से माफी मांगता हूं. उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने का जिक्र करते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया. पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में बिल पर बोलते हुए कहा, 'मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं. आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया. उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया. मैं इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं.'

नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ

पीएम ने कहा, 'बिल पास कराने के लिए जरूरी 66 परसेंट वोट हमें नहीं मिला हो... लेकिन मैं जानता हूं, देश की 100 परसेंट नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां, ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगी.'उन्होंने कहा, 'कांग्रेस हमेशा से हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही. लटकाना, भटकाना, अटकाना... यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, वर्क कल्चर रहा है.'

टीएमसी-कांग्रेस महिला विरोधी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही महिला विरोधी हैं. ये देश की नारी शक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती.' प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने नारी शक्ति वंदन बिल का विरोध कर लोहिया जी के आदर्शों को रौंद दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है. लेकिन कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है।

विपक्ष का सरकार पर वार, सीट बढ़ोतरी को लेकर साधा निशाना

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान 2029 से लागू करने वाले संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में पास न हो पाने के बाद राजनीति तेज हो गई है. जहां एक ओर सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बोलकर घेर रही है तो वही विपक्ष डेलिमिटेशन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. इस पूरी चर्चा के बीच विपक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि सरकार मौखिक रूप से कह रही है कि सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, लेकिन बिल में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था.

इस मामले पर सरकार के सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई कि इसका उल्लेख करना तकनीकी रूप से ठीक नहीं. इस संविधान (131वां संशोधन) विधेयक में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. इस पर सरकार के शीर्ष सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि विधेयक की भाषा और संवैधानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसा उल्लेख करना तकनीकी रूप से उचित नहीं था.

विधेयक को लेकर जरूरी जानकारी

सूत्रों के अनुसार, किसी भी विधेयक में केवल स्पष्ट, ठोस और निश्चित प्रावधानों का ही उल्लेख किया जाता है. लगभग जैसे सामान्य अभिव्यक्तियों को विधायी भाषा में शामिल करना उपयुक्त नहीं माना जाता क्योंकि इससे व्याख्या में अस्पष्टता और कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि 50 प्रतिशत वृद्धि का सीधा उल्लेख व्यावहारिक स्तर पर भी समस्याएं पैदा करता. देश के कई राज्यों में लोकसभा या विधानसभा सीटों की संख्या विषम है. ऐसे में 50 प्रतिशत वृद्धि लागू करने पर सीटों की संख्या पूर्ण नहीं बनती, जबकि किसी भी सदन में आधी सीट का अस्तित्व संभव नहीं है.

महिला आरक्षण के विरोध का सवाल ही नहीं उठताः ममता

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद में फेल होने पर बीते रोज पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दलों पर जमकर निशाना साधा. इस पर विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करना चुना. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है. संसद और राज्य विधानसभा दोनों में ही हमारी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात सबसे अधिक है. लोकसभा में हमारे 37.9% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं. राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्यों को मनोनीत किया है. महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और न कभी उठा है. उन्होंने आगे कहा कि हम जिस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वह है परिसीमन प्रक्रिया।

पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल

संसद के गलियारों में शुक्रवार का दिन एक बड़े सियासी उलटफेर का गवाह बना. मोदी सरकार के लिए पिछले 12 सालों में यह पहला मौका था, जब लोकसभा में कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक गिर गया. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तेजी से लागू करने और परिसीमन के साथ जोड़कर पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक को वह जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, जो संवैधानिक बदलावों के लिए अनिवार्य होता है. इस हार ने सत्ता और विपक्ष के बीच नई तकरार पैदा कर दी है. आइए जानें कि पहली बार इसे कब लाया गया था और तब से अब तक यह कितनी बार खारिज हुआ.

संसद में गिरी नारी शक्ति की उम्मीद

शुक्रवार की शाम लोकसभा में जो हुआ, वह भारतीय संसदीय इतिहास में एक अहम घटना बन गई है. महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन (परिसीमन) के साथ जोड़कर पेश किए गए इस 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर लंबी बहस हुई. मतदान के बाद जब परिणाम आया, तो सरकार के लिए स्थिति स्पष्ट थी. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 मत दर्ज किए गए. संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना जरूरी था, जिसे यह विधेयक हासिल नहीं कर पाया.

पहली बार कब आया यह बिल?

महिला आरक्षण का सफर आज का नहीं, बल्कि 30 साल पुराना है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि पहली बार यह बिल 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान संसद में पेश किया गया था. तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सत्ता के गलियारों में बहस का केंद्र रहा है. 1996 में जब इसे 81वें संविधान संशोधन के तौर पर लाया गया था, तभी सरकार अस्थिर हो गई और 11वीं लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ सका था. उस समय से यह एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका समाधान आज भी राजनीति के दांव-पेच में उलझा हुआ है.

कितनी बार हुई इस बिल को पास कराने की नाकाम कोशिशें?

1996 के बाद यह बिल बार-बार सदन में आया और बार-बार खारिज होता रहा. साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पेश किया, लेकिन सहमति के अभाव में यह ठंडे बस्ते में चला गया. इसके बाद 1999 में दोबारा प्रयास हुआ, फिर 2003 और 2004 में भी इसे लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार परिणाम वही रहा, राजनीतिक विरोध और हंगामा. यह दौर दिखाता है कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर कोई भी दल एकमत होने में नाकाम रहा.

बोइंग 787-8 में मिलेगा लग्जरी एक्सपीरियंस, किए गए बड़े बदलाव

एअर इंडिया का बड़ा मेकओवर!

एअर इंडिया ने अपने बोइंग 787-8 विमान को पूरी तरह से अंदर से नया रूप दे दिया है. पहले जहां टूटी सीटें, खराब स्क्रीन और वाई-फाई की कमी जैसी समस्याएं थीं, अब वह सब खत्म करने की कोशिश की गई है. एयरलाइन का पहला बदला हुआ विमान VT-ANT दिल्ली पहुंच चुका है और इसके साथ ही एअर इंडिया के बदलाव की नई शुरुआत मानी जा रही है.

एअर इंडिया के नए विमान में पहले की तरह दो नहीं, बल्कि तीन क्लास की सुविधा दी गई है. बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी. बिजनेस क्लास में 20 सीटें हैं, जो 1-2-1 लेआउट में लगाई गई हैं. इसमें यात्रियों को प्राइवेट स्पेस मिलता है, सीट पूरी तरह बेड में बदल जाती है और सामने बड़ी 17 इंच की 4K स्क्रीन दी गई है. इससे सफर ज्यादा आरामदायक और बेहतर हो गया है. प्रीमियम इकोनॉमी में भी 20 सीटें हैं, जो उन यात्रियों के लिए हैं जो सामान्य इकोनॉमी से थोड़ा बेहतर अनुभव चाहते हैं. इन सीटों के बीच ज्यादा जगह दी गई है, जिससे बैठने में आसानी होती है.

इकॉनमी क्लास में क्या आया बदलाव?

इकॉनमी क्लास में 205 सीटें हैं, जो 3-3-3 लेआउट में लगाई गई हैं. इसमें भी 11.6 इंच की 4K स्क्रीन दी गई है और मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A और USB-C दोनों तरह के पोर्ट दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी न हो. इस बदलाव का सबसे खास हिस्सा है कि अब इस विमान में वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी. एअर इंडिया ने इसमें वाईफाई सिस्टम लगाया है, जिससे लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. इसके अलावा सभी क्लास में नया एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें बेहतर स्क्रीन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है. इस पूरे बदलाव में काफी मेहनत लगी है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में बोइंग के सेंटर पर इस एक विमान को बदलने में करीब 45 दिन लगे और हजारों घंटे काम किया गया. विमान के अंदर सीट, लाइट, फर्श, दीवार और यहां तक कि खुलने तक सब कुछ नया कर दिया गया. काम पूरा होने के बाद इस पर एअर इंडिया की नई पहचान के हिसाब से पेंट भी किया गया.

रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर

नई दिल्ली। रूस ने भारत को पिछले एक दशक का सबसे बड़ा सैन्य विमानन प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के तहत भारत में कम से कम 100 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन करने की बात कही गई है, साथ ही व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी शामिल है. यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारतीय वायुसेना (IAF) को लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल लगभग 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि आधिकारिक जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है. इस कमी को देखते हुए रूस इस स्थिति को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहता है. वह Su-57 को सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में पेश कर रहा है. रूस ने सुझाव दिया है कि इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक प्लांट में किया जाए, जहां पहले से Su-30MKI का लाइसेंस के तहत उत्पादन होता रहा है.

विजयी रथ पर सवार पंजाब ने लगाया जीत का पंच

प्रियांश-कोनोली ने छुड़ाए लखनऊ के छक्के

नई दिल्ली। युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य (93) की विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली (87) की शानदार पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के विरुद्ध छह विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह आईपीएल के 19वें सीजन में एक पारी का सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 250 रन बनाए थे। इसके अलावा यह पंजाब का आईपीएल में दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले पंजाब ने 2024 में कोलकाता के खिलाफ 262 रन बनाए थे। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 255 रन चेज करने उतरी लखनऊ की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी। पंजाब ने 54 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया। मौजूदा सीजन में पंजाब की यह 5वीं जीत है। 6 मैच खेल चुकी पंजाब 11 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है। पंजाब-कोलकाता का मैच रद हुआ था। इसके साथ ही पंजाब किंग्स आईपीएल के किसी भी सीजन के पहले 6 मैचों में अपराजित रहने वाली पहली टीम बन गई है। दूसरी ओर लखनऊ की यह लगातार तीसरी हार है।

लखनऊ ने किया बड़ा बदलाव

लखनऊ के सामने 255 रन का पहाड़ जैसा स्कोर था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया। मिचेल मार्श के साथ एडेन मार्करम नहीं आयुष बडोनी मैदान में उतरे। मार्श और बडोनी के बीच 36 गेंदों पर 61 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। पावरप्ले की आखिरी गेंद पर बडोनी (35) कैच आउट हुए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने मार्श के साथ रन गति को बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर 31 गेंदों पर 48 रन जोड़ भी लिए थे। इसके बाद लखनऊ को 2 बड़े झटके लगे। अर्शदीप सिंह ने 13वें ओवर में पंत (43) को और 16वें ओवर में मार्को यानसेन ने निकोलस पूरन (9) पवेलियन भेज दिया। फिफ्टी की ओर बढ़ रहे एडेन मार्करम (42) आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी रही और पावरप्ले में टीम ने एक विकेट पर 63 रन बना लिए थे। प्रभसिमरन सिंह का खाता नहीं खुला। इसके बाद मध्य ओवरों में आर्य और कोनोली ने लखनऊ के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया और सातवें से 11वें ओवर के बीच 66 रन जोड़े। प्रियांश ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से रन बनाए। उन्होंने फुल लेंथ गेंदों को मैदान के बीचोंबीच और कवर के ऊपर से शानदार शॉट्स में बदला, जबकि छोटी गेंदों पर पुल और हुक शॉट खेलकर गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरी ओर कोनोली ने भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लांग ऑफ और मिडविकेट की दिशा में शानदार छक्के जड़े। प्रियांश ने केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि कोनोली ने 35 गेंदों में अपना पचासा लगाया।

सूर्यकुमार यादव की छुट्टी, अय्यर बनेंगे टीम इंडिया के कप्तान

नई दिल्ली। 2028 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कैसी दिखेगी, इसको लेकर अभी से प्लान सामने आने लगे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. ताजा रिपोर्ट्स अनुसार चयन समिति श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कप्तानी सौंपना चाहती है. इसका मतलाब सूर्यकुमार यादव की टीम में जगह खतरे में पड़ती दिख रही है, जो कई महीनों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सूर्यकुमार यादव के बाद टी20 टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी जा सकती है. श्रेयस को इंडियन प्रीमियर लीग में कप्तानी का खूब सारा अनुभव है और IPL 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार BCCI के एक सूत्र ने बताया अय्यर ने आखिरी टी20 मैच साल 2023 में खेला था और वे अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्हें वापस बुलाकर अचानक कप्तानी सौंप देना बहुत बड़ा फैसला होगा. फिलहाल ध्यान 2027 ODI वर्ल्ड कप पर है, ऐसे में चयनकर्ताओं को टी20 की लीडरशिप को लेकर सोचने का समय मिल गया है.

श्रेयस अय्यर को कप्तानी में खूब सारा अनुभव है. 2018 में अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी मिली थी. उनकी ही कप्तानी में दिल्ली की टीम IPL 2020 के फाइनल तक पहुंची थी. 2022 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया और उसके 2 साल बाद 2024 में अय्यर की कप्तानी में KKR की टीम ने ट्रॉफी उठाई. उन्होंने पंजाब किंग्स की भी किस्मत बदल डाली है. जो पंजाब की टीम 2014 के बाद कभी फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई थी, श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार लीडरशिप स्किल्स के बलबूते पंजाब को 11 साल बाद फाइनल में पहुंचाया. अब IPL 2026 में भी अय्यर बतौर कप्तान बेहतरीन रहे हैं. अब तक पंजाब एकमात्र टीम है जो मौजूदा सीजन में अजेय रही है और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठी हुई है.

शराब ने भरा झारखंड का खजाना, दारू से ₹4013 करोड़ पहुंचा राजस्व

नई दिल्ली। झारखंड के आबकारी विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जुटाया है. विभाग ने इस दौरान 4013 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन किया, जो पहले के लगभग 2700 करोड़ रुपये के आंकड़े से काफी ज्यादा है. अब इसे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत भी माना जा रहा है. जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया जा रहा है. यह दिखाता है कि विभाग में बेहतर कामकाज, सख्त निगरानी और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है. रेवेन्यू बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई रही है. बता दें कि अवैध निर्माण बिक्री और ट्रांसपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखी गई है. साथ ही लगातार छापेमारी और कई अभियान चलाए गए. अलग-अलग इलाकों में मिलकर कार्रवाई की गई।

अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम

नई दिल्ली। भारत की पुरुष टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. कथित तौर पर अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा होना वाला है. अगरकर के सिलेक्टर बनने के बाद टीम इंडिया ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, जिसके चलते भारतीय बोर्ड उन्हें बड़ा इनाम देने के लिए तैयार दिख रहा है. बता दें कि अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म हो जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा. उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक चला जाएगा. फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

तीन ट्रॉफी जीती टीम इंडिया

अगरकर के चीफ सिलेक्टर बनने के बाद टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के रूप में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती. इसके अलावा मेन इन ब्लू ने 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था. रिपोर्ट में एक बीसीसीआई ऑफीशियल के हवाले से कहा गया, "अगरकर के कार्यकाल में टीम का सुचारू रूप से बदलाव हुआ और उन्होंने साहसिक निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं दिखाया. बोर्ड को लगा कि उन्हें अपना पद जारी रखना चाहिए. बीसीसीआई के पदाधिकारी आईपीएल मैचों के दौरान उनसे बातचीत करेंगे।

अदाणी को मिला गोरेगांव में 100000 करोड़ का प्रोजेक्ट

मुंबई। मुंबई में बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है. एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप को गोरेगांव (पश्चिम) स्थित मोतीलाल नगर के पुनर्विकास की जिम्मेदारी मिली हैं. यह इलाका करीब 143 एकड़ में फैला हुआ है. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के मास्टर प्लान के अनुसार, इस मेगा प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जा सकता है. इसे मुंबई के बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. जिससे कई परिवारों को नया आशियाना मिलने वाला हैं. इस प्रोजेक्ट में पुनर्वास और फ्री-सेल दोनों तरह के हिस्से शामिल होने वाले हैं. उम्मीद की जा रही है कि, इस प्रोजेक्ट के तहत इलाके को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास की योजना बनाई गई है. मास्टर प्लान के मुताबिक 3,702 योग्य निवासियों को 1,600 वर्गफुट के कार्पेट एरिया वाले मुफ्त फ्लैट दिए जाएंगे. वहीं 328 बिजनेस यूनिट्स को करीब 987 वर्गफुट की जगह दी जाएगी. इसके अलावा करीब 1,600 झुग्गी निवासियों को 300 वर्गफुट के घरों में बसाने की योजना है.

चेन्नई को झटका, आयुष म्हात्रे हुए IPL से बाहर!

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. एमएस धोनी पहले ही चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं, डेवाल्ड ब्रेविस भी इंजरी के चलते शुरूआती मैचों में नहीं खेले थे. अब टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को हैमस्ट्रिंग इंजरी ने जकड़ लिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ CSK की पारी के 5वें ओवर में आयुष की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, जिसके बाद वह जमीन पर बैठ गए थे. फिजियो उन्हें देखने आए, हालांकि इसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया लेकिन जल्द ही आउट हो गए. अब खबर आई है कि उन्हें 3 हफ्ते के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है. आयुष म्हात्रे IPL 2026 में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने दिल्ली के खिलाफ भी अर्धशतक (5) जड़ा था, जिसमे चेन्नई ने जीत दर्ज की थी. म्हात्रे ने केकेआर के खिलाफ महत्वपूर्ण 38 रन बनाए थे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी वह अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई।

सावधान! चांदी खरीदने वाले 30% लोग हुए ठगी का शिकार

आपकी चांदी भी तो 'नकली' नहीं?

नई दिल्ली। क्या आप भी चांदी खरीदते हैं, या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो सावधान हो जाइये, कहीं आप भी ठगी का शिकार ना हो जाए. क्योंकि हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार, पिछले पांच सालों में करीब 30 प्रतिशत से भी ज्यादा ग्राहक चांदी खरीदते समय ठगी या धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. ये आंकड़ा बताता है कि बाजार में कितनी पारदर्शिता है और साथ ही साथ ग्राहकों को सावधान रहने की भी हिदायत देता है.

चांदी पर हॉलमार्किंग

इस सर्वे में ये भी खुलासा हुआ है कि 93 प्रतिशत लोगों ने चांदी के सामान पर हॉलमार्किंग को जरूरी बनाने का समर्थन किया है. जिससे वो और उन जैसे अन्य कई लोग ठगी का शिकार ना हो पाएं. जिसके बाद सरकार ने भी चांदी के गहनों और सामानों के लिए हॉलमार्किंग शुरू की है, जिसे एक डिजिटल पहचान प्रणाली से जोड़ा गया है. ये व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू हुई, ताकि सामान की शुद्धता के बारे में पता चल सके. बता दें कि हॉलमार्किंग से सोने याचांदी की शुद्धता पर ऑफिशियल मुहर या निशानी लग जाती है. इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि, 'कुछ ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक, ग्राहक खुद भी BIS Care मोबाइल ऐप के जरिए कई जरूरी जानकारियां जैसे आर्टिकल टाइप, शुद्धता, हॉलमार्क की तारीख, जांच केंद्र की जानकारी और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वेरिफाई कर पाएंगे'.

10 में से 3 लोग होते हैं ठगी का शिकार

इस सर्वे में शामिल करीब 8 प्रतिशत लोगों ने बताया कि चांदी खरीदते समय उनके साथ एक बार धोखाधड़ी हुई. वहीं 42 प्रतिशत लोगों ने किसी भी तरह की ठगी की शकियत नहीं की है. जबकि 27 प्रतिशत लोगों ने इस बारे में साफतौर पर कुछ भी नहीं कहा. इसका मतलब है कि लगभग हर 10 में से 3 लोगों के साथ चांदी खरीदते वक्त ठगी या धोखाधड़ी होती है. इस सर्वे से पता चलता है कि हमें सोना या चांदी खरीदते वक्त कितना सतर्क रहना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की ठगी का शिकार ग्राहक ना हो सके. हर उपभोक्ता को विश्वसनीय या प्रमाणिक ज्वेलर के पास से ही चांदी खरीदना चाहिए और जाने से पहले इसकी जानकारी भी रखना चाहिए.

साप्ताहिक शहर सत्ता

महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस के खिलाफ BJP

CM बोले 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूटीं

शहर सत्ता/रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी। इसी कड़ी में लगातार छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरा गया, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ गद्दारी की है।

CM बोले- कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे बहुत दुखी मन से मीडिया के बीच आए हैं और 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण विपक्ष के रवैये की वजह से नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 57 प्रतिशत है और विधानसभा में भी 21-22 प्रतिशत नारी शक्ति है। इंडी गठबंधन के लोग अंग्रेजों की तरह "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाते हैं और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कहकर लोगों को बरगलाती है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है और देश की माता-बहनें सच्चाई जान चुकी हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की महिलाओं की उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने दिया जाएगा।

अरुण सिंह बोले- यह विपक्ष की काली करतूत

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी "काली करतूत" का परिचय दिया और बिल पास नहीं होने दिया। जब भी महिला अधिकार की बात आई, कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ गद्दारी की है और हमेशा उनके हितों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महिला बिल को फाड़ने तक का काम किया। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने हमेशा महिलाओं को गाली देने का काम किया। महिलाओं को इस बार पूरी आशा थी कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन बिल गिरने पर विपक्ष के लोगों ने तालियां बजाईं और खुशियां मनाईं, जबकि भाजपा के लोगों की आंखों में आंसू थे।

अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग चालबाज हैं और कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। संशोधन में दो-तिहाई बहुमत चाहिए था, इसलिए उम्मीद थी कि कांग्रेस और विपक्ष समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग समर्थन करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं होने नहीं दिया। जो नासमझ हो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझकर भी न समझे, वही काम कांग्रेस कर रही है। भाजपा के संविधान में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उल्लेख है।

जनता भाजपा सरकार के मंत्रियो को भी बादाम खिलाये मोदी गारंटी याद दिलाये

शहर सत्ता/रायपुर। बिलासपुर में बादाम खिलाने के बाद फ़ाईल मिलने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता को अब भाजपा सरकार मंत्रियो को बादाम खिलाकर मोदी की गारंटी याद दिलाना चाहिए। ढाई साल की सरकार में मलाई खाने में मंत्री इतना मशगूल हो गए है कि उन्हें जनता किये वादा को पूरा करने की याद नही आ रही है। मोदी गारंटी में 1लाख सरकारी नोकरी,57000 शिक्षकों की भर्ती,महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट का काम,500 रु में रसोई गैस सिलेंडर,5 लाख अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण,कालेज के छात्रों को निःशुल्क बस सेवा,महतारी वंदन योजना में सभी महिलाओं को 1 हजार रुपया महीना,18 लाख नया पीएम आवास,ग्राम पंचायतों नगद भुगतान और डिजिटल सेवा,पुलिस कर्मियों के लिए आवास,मितानिन एवं रसोइयां,सफाई कर्मियों की वेतन में 50% वृद्धि सहित अनेक गारंटी दी गई थी अब उन गारंटियों की भाजपा नेता और सरकार के मंत्रीयों को याद नही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ढाई साल की सरकार में प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल गई है जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे फ़ाईल गुमने पर अधिकारियों को बादाम खिलाकर याददाश्त दुरुस्त करने पड़ रहे है तब जाकर अधिकारी को चेत आ रहा है वही हाल सरकार के मंत्रियों का भी हो गया है।

राशन दुकानों में कतारे लगी सरकार उत्सव मना रही - कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। सरकार 7 अप्रैल से राशन दुकानो में 3 माह का चावल देने का प्रोपोगंडा कर रही लेकिन दुकानो में आम आदमी को राशन नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि दुकानों में सरकार पर्याप्त मात्रा में स्टाक नहीं पहुंचा पाई है। आम आदमी राशन दुकानों में घंटो लाइन लगाता है। उसके बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार का चावल उत्सव गरीब आदमी से भद्दा मजाक बन गया। अभी तक जितने चावल की जरूरत है उसका 30 प्रतिशत भी चावल राशन दुकानों में नहीं पहुंचा है। 31 लाख उपभोक्ताओं का राशन कार्ड केवाईसी के नाम पर काट दिया। अब चावल उत्सव मनाने का ढकोसला कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि पिछले पांच महीने से सरकार राशन दुकानों को नियमित राशन तो पहुंचा नहीं पायी है। पांच माह से राशन कार्डधारियों को चावल नहीं मिल रहा है और सरकार तीन महीने का चावल एकमुश्त देने का ढिंढोरा पीट कर चावल उत्सव मनाने जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक दुकानों में मात्र 30 प्रतिशत चावल ही उपलब्ध है, जब दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पाया है तो उपभोक्ता को कैसे चावल देगी सरकार? इस बात को कांग्रेस पहले से उठाते आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से पीडीएस के स्टॉक का सत्यापन ही नहीं हो रहा है।

भाजपा युवा मोर्चा रायपुर शहर की नई कार्यकारिणी घोषित

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में बीजेपी के युवा संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। संगठन में नई ऊर्जा और सक्रियता लाने के लिए शुभांकर द्विवेदी को रायपुर जिला उपाध्यक्ष और आयुष शर्मा को सह मीडिया प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति भाजयुमो जिला अध्यक्ष की अनुशंसा और प्रदेश नेतृत्व की सहमति के बाद की गई है। संगठन के इस फैसले को रायपुर शहर में युवाओं को अधिक संगठित करने और पार्टी की गतिविधियों को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नई टीम से उम्मीद की जा रही है कि वह आगामी समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाएगी।

निष्ठा और सक्रियता का मिला प्रतिफल

शुभांकर द्विवेदी और आयुष शर्मा लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी रही है। दोनों नेताओं ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उनकी कार्यशैली, सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह उनके अब तक के कार्यों का सम्मान भी है और भविष्य की जिम्मेदारी भी।

युवाओं को जोड़ने पर रहेगा फोकस

नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही संगठन ने यह संकेत दिया है कि अब युवाओं को जोड़ने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन का आभार जताते हुए कहा कि, वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे।

महिला आरक्षण बिल को लेकर अभियान चलाएगी कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस अब प्रदेशभर में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। 20 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। जिसके बाद आंदोलन और जन जागरण की रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, पार्टी को अपना नाम बदलकर "भारतीय झूठा पार्टी" रख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे लागू करने के बजाय परिसीमन के बहाने टाल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर परिसीमन बिल को आगे बढ़ाना चाहती है, जो पूरी तरह गलत है।

लोकसभा में पास नहीं हो सका बिल

महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। इस प्रस्ताव में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया था।

पीएम मोदी ने मांगी माफी, विपक्ष पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बिल पास नहीं हो पाने पर माताओं-बहनों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि संशोधन नहीं हो सका, जिसके लिए वे क्षमा चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पार्टियों के लिए दल हित, देशहित से बड़ा हो गया है, जिसका नुकसान नारी शक्ति को उठाना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति के कारण महिलाओं के अधिकारों को झटका लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण प्रस्ताव गिरने के बाद विपक्ष ने खुशी जताई, जबकि देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें संसद से जुड़ी थीं। नारी शक्ति इस अपमान को नहीं भूलेगी और इस पूरे घटनाक्रम को याद रखेगी।

अभियान से बनाएंगे माहौल

कांग्रेस का कहना है कि वह इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में माहौल बनाएगी और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक, यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है।

साय सरकार में छोटे-छोटे कार्यों के लोगो को भटकना पड़ रहा - कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे काम के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगो के नामांतरण, फौत, त्रुटि सुधार के लाखो आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि लाखों लोगों को सरकार के पास सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के कामो के लिये आवेदन लेकर भटकना पड़ता है। साय सरकार लोगो के मूलभूत काम को भी नहीं कर पा रही है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अब तक 135 लाख करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। बिजली कटौती, पेयजल की समस्या, शिक्षकों की कमी, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, व्यापारी अनियमित जीएसटी से परेशान है। प्रदेश में मात्र 33 प्रतिशत स्टील उद्योग चल रहे हैं बांकी महंगी बिजली एवं प्रशासनिक अराजकता के चलते बंद हो गए है। अनियमित कर्मचारी, दिव्यांगजन वादाखिलाफी से त्रस्त है। गरीबों को चावल के लिए राशन दुकानों के चक्कर काटना पड़ता है, महतारी वंदन के 1000 रू. के लिए माताओं, बहनों को धूप में केवाईसी कराने घंटों खड़े होना पड़ रहा, 500 रू. में गैस सिलेंडर का वादा जुमला निकला।

सरकार में बैठे लोग कोल परिवहन पर 100 रू. टन लेबी ले रहे : सुशील

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध माइनिंग का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फल-फूल रहा है। खनन माफिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतने बेफिक्र हो गए हैं की खुलेआम माइनिंग अधिकारियों कर्मचारियों की पिटाई कर रहे हैं। बलरामपुर में अवैध उत्खनन रोकने पर विभाग के अधिकारियों की पिटाई कर दी गयी, इसके पहले गरियाबंद में खनिज इंस्पेक्टर सहित अनेकों कर्मचारियों की पिटाई रेत माफिया ने किया था। रायपुर जिले के आरंग के पास समोदा के हरदीडीह रेत घाट में खनिज विभाग के 16 अधिकारी, कर्मचारियों को अवैध खनन माफिया के लोगों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। उसके बाद खनिज विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सील की गई मशीन खुलवाई गई और कार्यवाही का पत्रक भी फाड़ दिया।

सशक्त महिलाओं से बनता है मजबूत राज्यः राजवाड़े

'लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ट' से आत्मनिर्भरता को मिली नई रफ्तार

रायपुर। महिला सशक्तिकरण को राज्य के समग्र विकास की आधारशिला बताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और पूरा राज्य मजबूत होता है। उन्होंने अपने निवास, नया रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय 'लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ट' वितरण कार्यक्रम में यह उद्बोधन देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभिन्न स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को 'लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ट' वितरित किए। इस अवसर पर श्रीमती शैलेन्द्री कुर्रे, श्रीमती डिगेश्वरी निषाद, श्रीमती अनिता ताण्डी, श्रीमती सुमन वर्मा, श्रीमती दीपाली राजपूत, श्रीमती दीपा सोनी, श्रीमती कामिनी बोथरा, श्रीमती सुभद्रा निर्मलकर, श्रीमती गीता साहू एवं श्रीमती प्रीति साहू सहित कई हितग्राही उपस्थित रहीं। मंत्री ने बताया कि 'मिलेट्स कार्ट' अभियान महिलाओं के लिए स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। कांकेर जिला के नरहरपुर ग्राम की श्रीमती लोकेश्वरी रसिया और अन्य महिलाये प्रतिदिन 2 से 3 हजार रुपये तक तथा प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, क्षमता और समान अवसर विकसित करने की सतत प्रक्रिया है। जब महिलाएं शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर होती हैं, तो परिवार और समाज दोनों का समग्र विकास होता है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महिला कोष योजना और सक्षम योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला कोष योजना के तहत वर्ष 2003 से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पहली बार 2 लाख रुपये तक तथा समय पर पुनर्भुगतान करने पर दूसरी बार 6 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा 12.77 करोड़ रुपये के पुराने ऋण माफ किए गए, जिससे लगभग 1 लाख महिलाएं पुनः ऋण लेने के लिए पात्र हुईं।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में 10,500 महिलाओं को 10.70 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, वहीं 2023-24 में 2500 समूहों को 31 करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सक्षम योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2.63 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर महिलाओं को व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से महिलाएं पापड़ निर्माण, श्रृंगार सामग्री, किराना व्यवसाय सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च 2026) के अवसर पर बस्तर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा 'लक्ष्मी मिलेट्स कार्ट' अभियान का शुभारंभ किया गया था।

माओवाद के बाद विकास की नई राह पुसपाल बनेगा ईको-टूरिज्म हब

- **रिसॉर्ट और ओपन रेस्टोरेंट से बढ़ेगा पर्यटन और आजीविका के साधन : केदार कश्यप**

रायपुर। कोण्डागांव जिले के पुसपाल क्षेत्र से माओवाद खत्म होने के बाद अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है। वर्षों तक प्रभावित रहने के कारण जहां पर्यटन गतिविधियां ठप थीं, वहीं अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है और पर्यटन की संभावनाएं फिर से जीवंत हो गई हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने ग्राम परौदा में लगभग एक करोड़ 45 लाख 96 हजार रूपए की लागत से बनने वाले ईको-टूरिज्म रिसॉर्ट का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही पुसपाल क्षेत्र में ही एक करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नदी तट पर बनने वाले ओपन रेस्टोरेंट का भी भूमिपूजन किया।

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पुसपाल को विकसित करने का उद्देश्य कोण्डागांव–बस्तर ईको-टूरिज्म सर्किट को मजबूत बनाना है। अभी तक पर्यटक टाटामारी और चित्रकूट तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब पुसपाल में नई गतिविधियां शुरू होने से पर्यटन का दायरा भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि यहां भंवरडीह नदी में एटीवी राइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग और बांस राफ्टिंग जैसी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। साथ ही पुसपाल वैली में व्यू पॉइंट से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखने के साथ पर्यटक ईको-कॉटेज में रात्रि में सितारों से भरे आकाश का आनंद लेते हुए विश्राम कर सकेंगे।

150 मीटर लंबी सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती

रायपुर। कोरिया जिला में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार दूसरे दिन व्यापक कार्रवाई की। रायपुर से पहुंची सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने रविवार को देवखोल और भालूमाड़ा क्षेत्रों का निरीक्षण कर अवैध खनन स्थलों का चिन्हांकन किया और उन्हें ब्लास्टिंग कर स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिए।

इस दौरान जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, जिसमें खनिज, वन, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। टीम ने बताया कि निरीक्षण के समय मौके पर कोई कोयला या खनन सामग्री नहीं मिली, लेकिन पूर्व में यहां बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। इस कार्रवाई से एक दिन पहले, शनिवार को संयुक्त टीम ने पटना तहसील अंतर्गत देवखोल जंगल में सघन अभियान चलाया था। इस दौरान अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। साथ ही कई अवैध सुरंगों को ध्वस्त किया गया, जिनका उपयोग लंबे समय से कोयला निकालने के लिए किया जा रहा था। अभियान के दौरान टीम ने करीब 150 लंबी सुरंगों के भीतर प्रवेश कर न केवल कोयला बरामद किया था, बल्कि खनन में उपयोग होने वाले उपकरण और बड़ी मात्रा में बिजली के तार भी जब्त किए थे। कार्रवाई में कोरिया के अलावा सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिलों के खनिज अधिकारी, स्थानीय पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे।

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से बस्तर को मिलेगा वैश्विक कनेक्शन

बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

रायपुर। बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130 CD) एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान कर लैंड-लॉक्ड क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करेगा।

दुर्गम घाटों से मुक्ति और समय की बड़ी बचत

वर्तमान में जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 से 9 घंटे का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि डीजल की खपत और मेंटेनेंस के लिहाज से भी खर्चीला है। नया कॉरिडोर इस यात्रा को मात्र 3.5 से 4 घंटे में समेट देगा। सीधा और घाट-मुक्त रास्ता होने के कारण वाहनों का परिचालन खर्च काफी कम हो जाएगा, जिससे परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

नबरंगपुर इंटरचेंज: बस्तर का प्रवेश द्वार

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130 CD) छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव जिलों से गुजर रहा है। जगदलपुर मुख्यालय को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर का दासपुर इंटरचेंज महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। जगदलपुर का ट्रैफिक मात्र 50-60 किमी का सफर तय कर नबरंगपुर इंटरचेंज के माध्यम से रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो सकेगा, जिससे बस्तर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ जाएगा।

बस्तरिया ब्रांड का अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश

इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बस्तर की अरेबिका कॉफी, जैविक इमली, महुआ उत्पाद और प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुँचाना सुगम होगा। कम लॉजिस्टिक लागत के कारण ये उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय किसानों, संग्रहकर्ताओं और शिल्पकारों को उनकी उपज का बेहतर अंतरराष्ट्रीय मूल्य मिल सकेगा। बस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आकांक्षी जिलों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं इन सुदूर क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।

छालीवुड में बरसेगा प्यार ही प्यार आयुष और तिरांजलि करेंगे डेब्यू

- मोला मुम्बई घुमा दे राजा और डोंट टच माय गगरी गाना हिट
- 8 मई को छत्तीसगढ़ी फिल्म 'मोला लव होगे' रिलीज़ होगी
- जून 2026 में 'महूँ दिलवाला तहूँ दिलवाली' बड़े परदे पर

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी है। जून की तपती गर्मी में प्यार भरे मधुर गीत और एक अलग तरह की प्रेम कहानी छालीवुड प्रेमियों के दिलों को ठंडक देगी। जी हां, 8 मई को छत्तीसगढ़ी फिल्म 'मोला लव होगे' और जून 2026 में 'महूँ दिलवाला तहूँ दिलवाली' संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बड़े परदे पर प्रदर्शित होगी। 'मोला लव होगे' से छालीवुड प्रेमियों को दो युवा और तरोताज़ा चेहरों के बीच प्यार की अनूठी केमेस्ट्री देखने को मिलेगी। दोनों ही छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बतौर चॉकलेटी हीरो आयुष राजवैद्य अपने अभिनय, रोमेंटिक गानों और प्यार की हद तक प्यार करते दिखेंगे। नए हीरो संग बतौर नव अभिनेत्री तिरांजलि गोस्वामी भी दिखाई देंगी। आयुष रायपुर से हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली, ऊर्जावान हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। तिरांजलि गोस्वामी भानुप्रतापपुर से हैं और उनकी भी पहली फिल्म होगी 'मोला लव होगे'।

8 मई को छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगे के हिट गाने

फिल्म के निर्माता निर्देशक अनुमोद राजवैद्य हैं। अनुमोद का कहना है कि फिल्म के दो गाने अभी से यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं। इसमें -मोला मुम्बई घुमा दे राजा और डोंट टच माय गगरी गाना सभी की जुबान पर अभी से आ गया है। अन्य मधुर गानें भी संगीत प्रेमियों को फ्रेशनेस का एहसास कराएंगे। बता दें आयुष छइयां भुइयां फेम अदाकारा प्रीति के पुत्र हैं।

जून में धूम मचाने आएगी "महू दिलवाला तहूं दिलवाली"

इस फिल्म को गरियाबंद की खूबसूरत वादियों में शूट किया गया है। फिल्म की कहानी और पटकथा नीरज विक्रम ने लिखा है। नीरज लंबे समय से मुंबई में फेमस कार्टून चैनल सीरीज मोटू पतलू की कहानी लिखते आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी नीरज विक्रम ने किया है। इस फिल्म का गाना - जावत हस अकेला गोरी .... बहुत ही अच्छा बन पड़ा है जो जल्दी ही धूम मचाएगा और लोग इसे गुनगुनाते दिखेंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रशंसक और पूरा छालीवुड दोनों फिल्मों के इंतज़ार में बेक़रार हैं। मन होथे वो अचरा म तोर, जड़ देहूँ सितारा गिन गिन के...देखे हावव जब से तोला राजा, हारे हाव दिल अब मैं आजा

टीवी से दूरी बनाने के बाद भी जन्नत हैं करोड़ों की मालकिन

जन्नत जुबैर उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने बेहद ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. लेकिन, एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी थी. जन्नत अब 24 साल की हो चुकी हैं और करोड़ों की मालकिन बन गई हैं. वैसे तो एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत की थी. लेकिन, कई सालों तक उन्होंने टीवी से दूरी बनाकर रखी, फिर भी करोड़ों की मालकिन हैं. जन्नत जुबैर ने जब करियर की शुरुआत की थी, तब उनकी उम्र महज 7 साल थी. आज भी उन्हें उनके शो फुलवा के लिए याद किया जाता है. 2018 तक टीवी पर काम करने के बाद एक्ट्रेस ने इससे दूरी बना ली.

पहले ही टीवी से दूरी बनाने की कर ली है प्लानिंग

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में जन्नत जुबैर ने कहा था कि टीवी छोड़ने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगी थी. क्योंकि, उन्हें पूरे दिन काम करने की आदत लग चुकी थी. ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें. उसके बाद एक्ट्रेस ने डिजिटल क्रिशन की तरफ रुख किया. उन्होंने अपने भाई के संग मिलकर वीडियोज बनाना शुरू किया. जन्नत जुबैर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, 'मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं डेली सोप छोड़ दूंगी. लेकिन जब मैंने अपने आखिरी शो के बाद आखिरकार ऐसा किया, तो मैं बहुत बेचैन थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताईं. मैं टीनेजर थी. मुझे दिन भर काम करने की आदत थी. फिर बिल्कुल नया रास्ता चुना

पहली प्रेग्नेंसी में काफी मुश्किल दौर से गुजरी थीं दीपिका

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट कर फैंस को चौंका दिया है. ये खुशखबरी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस से लेकर सैलेब्स तक कपल को बधाई देने में लगे हुए हैं. इसी बीच दीपिका पादुकोण का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली प्रेग्नेंसी के एक्सपीरियंस को शेयर किया था. दरअसल, उन्होंने आखिरी महीनों में झेली गई इमोशनल और फिजिकल चुनौतियों के बारे में बात की थी. Marie Claire को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने बताया था कि उन्हें प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था.

दुआ नाम रखने के पीछे की वजह

दीपिका ने कहा था, 'प्रेग्नेंसी के आठ-नौ महीनों और डिलीवरी के दौरान मैंने काफी कुछ झेला था. 'इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का नाम रखने के पीछे की सोच के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी था पहले अपनी बच्ची को गोद में लेना, उसे इस दुनिया को महसूस करने देना और उसकी पर्सनैलिटी को धीरे-धीरे विकसित होने देना. दीपिका के अनुसार उनकी बेटी का नाम उनके लिए बेहद ही खास है और ये उस फीलिंग को दर्शाता है कि वो उनके लिए क्या मायने रखती है. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 29 फरवरी 2024 को फैंस के संग प्रेग्नेंसी की खबरें शेयर की थीं. उस दौरान कपल ने पिंक और ब्लू कलर के बेबी आइटम्स की तस्वीर शेयर की थी. उसके बाद सितंबर 2024 में उन्होंने दुआ का वेलकम किया था.

अब 19 अप्रैल 2026 को दीपिका और रणवीर ने एक बार फिर से फैंस के संग बड़ी खुशखबरी शेयर की है. दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के लिए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उनकी बेटी दुआ नजर आ रही हैं. दुआ उस पोस्ट में प्रेग्नेंसी टेस्ट कीट पकड़े दिख रही हैं. दीपिका पादुकोण की वर्क फ्रंट की बात करें तो वो शाहरुख खान के संग किंग और अल्लू अर्जुन के संग राका में नजर आने वाली हैं.

साध्वी सतीश सैल ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब

उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए 'फेमिना मिस इंडिया 2026' का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल के सिर सजा है और इसी के साथ 61वें ब्यूटी पेजेंट को नई मिस इंडिया भी मिल रही है. खिताब जीतने के बाद ही सोशल मीडिया पर साध्वी सतीश सैल छाई हुई हैं, जबकि महाराष्ट्र की राजनंदिनी फर्स्ट रनर-अप रही, और सेकंड रनर-अप जम्मू-कश्मीर की अद्वैता रही. ब्यूटी पेजेंट में चार-चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों को देखा गया.

61वें फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले में पहुंची एक्ट्रेस ज़ीनत अमान कहती हैं, "भुवनेश्वर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह एक खूबसूरत जगह है, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है. मेरे लिए फेमिना मिस इंडिया बहुत खास रहा है क्योंकि मैंने भी इसी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और भारत को रिप्रेजेंट किया था." बॉलीवुड एक्ट्रेस और निर्माता नेहा धूपिया ने आईएएनएस से कहा,, "भुवनेश्वर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. इस आयोजन की भव्यता देखकर बहुत खुशी हो रही है. यह कितना खास पल है. हमें यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, और यहां होना वाकई अद्भुत है."

ब्यूटी पेजेंट में पहुंचे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस के लिए शो बहुत खास रहा. उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "यह फेमिना मिस इंडिया की कहानी है. यह फेमिना मिस इंडिया 2026 का 61वां संस्करण है और भुवनेश्वर मेजबान शहर है. मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है. मैं यहां कई बार आ चुका हूं. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यहां सिर्फ खूबसूरती ही मायने नहीं रखती, बल्कि व्यक्तित्व भी मायने रखता है." वहीं बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल ने ब्यूटी पेजेंट में अपनी खूबसूरत आवाज से सभी का दिल धड़का दिया. सिंगर के लिए भुवनेश्वर आना भी खास है, क्योंकि ये स्थान उन्हें घर जैसा फील देता है. उन्होंने कहा, "भुवनेश्वर मुझे घर जैसा लगता है. मैं अक्सर यहां शो के लिए आता हूं. इस बार फेमिना मिस इंडिया का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में हो रहा है, जो हम सभी के लिए एक बहुत ही खास पल है.

'खतरों के खिलाड़ी 15' में होगी जैस्मीन की वापसी

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को लेकर दर्शकों में इन दिनों काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से ये शो टीवी पर वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस नए सीजन में पहले से ज्यादा एडवेंचर और खतरनाक स्टंट्स देखने को मिलने वाला है. पिछले कई सालों से ये शो दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. खतरनाक स्टंट्स और मुश्किल टास्क के लिए पॉपुलर ये शो एक्शन, डर, इमोशनल स्ट्रेंथ और तगड़े कॉम्पिटिशन का कॉम्बिनेशन है. हर सीजन में सेलिब्रिटीज अपनी सीमाओं को पार करते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जिसे देखना दर्शक काफी पसंद करते हैं. इस बार खबरें आ रही हैं कि इस सीजन में जैस्मिन भसीन भी नजर आने वाली हैं. Indiaforums के अनुसार जैस्मिन को खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स ने अप्रोच किया है.

भील समुदाय में मृतक स्तम्भ की विशेषता

डा. नीलिमा गुप्ता

आदिवासी अंचल में भील समुदाय के लोग किसी खास व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके सम्मान में स्मारक बनाने की प्रथा प्रचलित है, जिसे गाया, गाता या गातला कहा जाता है। इनके द्वारा निर्मित काष काष्ठ तथा पाषाण गाथा के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं।

पहले लकड़ी के गाथा बनाते थे, किंतु आजकल पत्थर के गाथा बनाए जाते हैं जो अधिक टिकाऊ होते हैं। राजसी वेशभूषा में खड़े वीर पुरुष की मुख्य आकृति में उसे घुटना झुकाए, म्यान से तलवार या बंदूक से अज्ञात वस्तु पर निशाना लगाते, कमर में तलवार लटके खड़ा बनाया जाता है। खी के स्मृति स्तम्भ को सती कहा जाता है। स्त्री के लिए काले पत्थर का सादी ही बनाते हैं। कुंवारी सती में केवल एक स्त्री तथा विवाहित स्त्री के साथ उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। कभी कभी अकाल मृत्यु के कारणों के अनुसार भी मृतक स्तम्भबनाए जाते हैं। स्मृति गाथा स्तम्भ भील जीवन एवं संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। आनुष्ठानिक क्रिया विधियों, मिथकीय पराभौतिक शक्तियों से परिपूर्ण गाथा लौकिक जीवित मानवों और पारलौकिक आत्माओं के बीच सेतु का निर्माण कर एक तादातम्य स्थापित करता है।

सुगघर सुरता देवाथे रायपुर के डे भवन

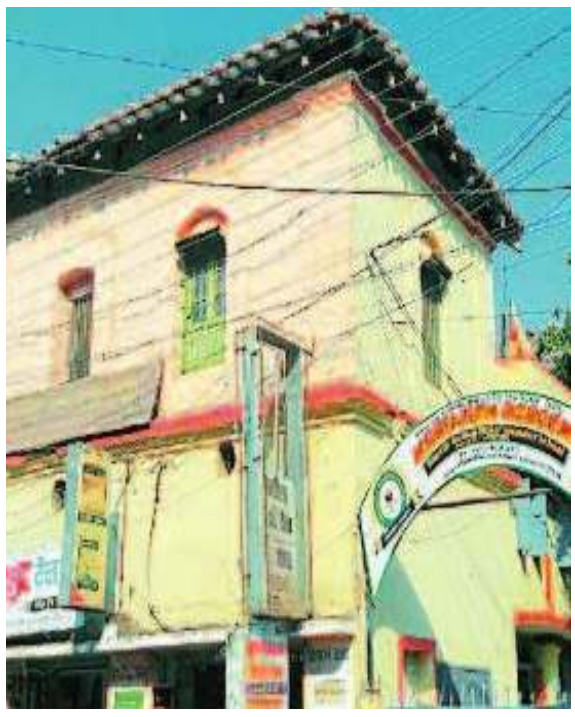

डा. सुनीत रमेन्द्र मिश्र

हमर रायपुर शहर म एक ले बढ़ के एक योग्यता वाले रहिन हे, जउन देश दुनिया म नाव कमइन। भूतनाथ डे शहर के पहिली सियान वकील अउ नगर पालिका के सभापति रहिन। उकरे घर म दू बछर तक नरेंद्रनाथ दत्त (विवेकानंद) के माता पिता, भाई बहिनी मन रिहिन। इहि च हरिनाथ डे जी के भाषा साहित्य म बड़ नाव रिहिस। उन छत्तीस भाषा के जानकार रिहिन। अउ तैतीस बछर के उमर म जर बुखार आय ले उनकर इंतकाल होगे। वोमन ढाका विश्वविद्यालय म प्रोफेसर रिहिन। अउ राष्ट्रीय ग्रन्थागार कलकत्ता म पहिली हिंदुस्तानी ग्रन्थपाल रिहिन। लार्ड कर्जन तक उकर तारीफ करे रिहिन। डे भवन बुढ़ापारा आज हमला सब जुन्ना बात के सुरता देवात दिखत हवय। एहा 1877 के बात आय। अइसन अउ कतको सुरता हमर रायपुर शहर ह देवात हवय जेन ह हमर बर गरब के बात आय।

बीसवीं शताब्दी का छत्तीसगढ़

किशोर कुमार अग्रवाल

सन 1903 में मध्य प्रान्त के साथ बरार को सम्बद्ध किए जाने का यहां की राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस समय नेताओं के लोकमान्य तिलक से संपर्क होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। उन्हें स्वाभाविक रूप से उग्र राष्ट्रीयता में अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाई दिया, और ब्रिटिश शासन के प्रति पैरले असंतोष को प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर मिला। उल्लेखनीय है कि इसी परिषद के 1907 में रायपुर में हुए तृतीय सम्मेलन में दो विपरीत विचार वाले दल के बीच जो फूट पड़ी उसका व्यापक स्वरुप सूरत की कांग्रेस अधिवेशन में भी देखने को मिला। 1907 में डी छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे द्वारा नागपुर में हिन्दी केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करना भी यह सिद्ध करता है कि धीरे धीरे प्रान्त की राजनीति में इस क्षेत्र का नेतृत्व स्वीकार किया जाने लगा था।

अंचल के शिलाखंडों में प्रसिद्ध चित्रांकन

शिलाचित्रों के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। रायगढ़ से लगभग 10 मील की दूरी पर कबरा पहाड़ आग्नेय कोण में स्थित है। यहां की सारी चित्रकारी लाल रंग से हुई है। वैज्ञानिक एवं पुरावेत्ताओं के मतानुसार प्रागैतिहासिक कालीन मानव पहाड़ों और गुफाओं में रहते थे। वे वन प्रदेश में जानवरों का शिकार कर तथा कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इन गुफा मानवों को चित्रकला का प्रारंभिक ज्ञान व रंगों की जानकारी थी, जिसका उपयोग कर चट्टानों पर चित्र खिंचा करते थे। चट्टानों की भित्तियों पर बनाए गए विभिन्न शिकार जन्य परिस्थितियों पर आधारित यह भित्ति चित्र इनके जीवन के प्रतिबिम्ब थे। तत्कालीन भित्तिचित्रों में घड़याल, सांभर तथा अन्य पशुओं के साथ साथ पंक्ति बद्ध मनुष्यों के नृत्यरत चित्र भी दिखाई देते हैं। जंगलों से घिरे पर्वतों और चट्टानों पर प्राचीन काल के मानव की चित्रकला के अवशेष यत्र तत्र प्राप्त होते रहते हैं। यह सभी शैलचित्र बीस हजार से पचास हजार वर्ष से भी पहले के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

खूबसूरत एवं मनोरम प्राकृतिक जलप्रपात देवधारा

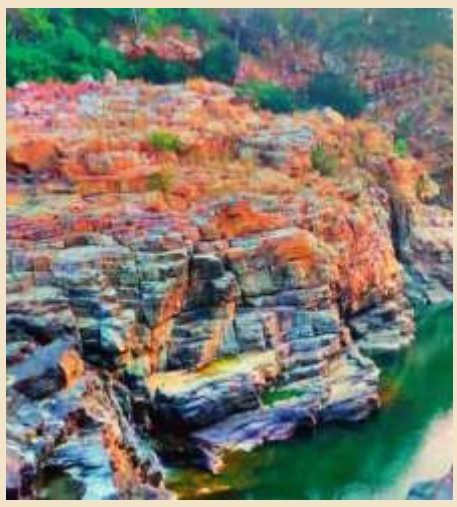

डा. डी. पी. देशमुख

जिला मुख्यालय गरियाबंद से लगभग 80 कि.मी. दूरी पर मैनपुर विकासखंड के कुल्हाड़ीघाट ग्राम पंचायत में स्थित देवधारा जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुकून-शांति का अद्भुत स्थल है। इंद्रावन नदी पर स्थित यह जलप्रपात दो पहाड़ी के चट्टानों के बीच से 70 फुट की ऊंचाई से जलधारा के रूप में नीचे गिरती है तब यहां विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुर्गम उदंती अभ्यारण्य के बीहड़ जंगल क्षेत्र स्थित यह खूबसूरत स्थल प्रकृति के बीच शांति, सुंदरता व सुकून का मनमोहक स्थल है। यात्रा के दौरान रास्ते भर साजा, बीजा, लेंडिया, हल्दू, सरई जैसे पेड़ और हरे-भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यह क्षेत्र राजकीय पशु वनवासी वनभैसों के लिए भी विख्यात है। प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती यह जलप्रपात इंद्रावन नदी की धारा फुटकर जब चट्टानों पर गिरती है तब सम्पूर्ण दृश्य मानों प्राकृतिक चित्रकला का अहसास होता है जो न केवल आंखों को सुकून देता है बल्कि दिल और आत्मा को भी तरोताजा कर देता है। नदी के ऊपर भाई दाहरा, हाथ दाहरा, नागरशील और कई रमणीक सरोवर है, जहां वर्ष भर भरपूर पानी भरा रहता है। धार्मिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण स्थल है। विभिन्न पर्व विशेष पर यहां लगने वाला मेला श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र रहता है।

परिवहन में नियम का खेल, सिस्टम फेल, विभाग कर रहा 'चौतरफा' वसूली

साहब! डेथ व्हीकल से तो टैक्स छोड़ देते...

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव
मोबाईल नंबर 9827181979

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की नीतियां और करारोपण विवादों में हैं। अकेले परिवहन विभाग ही शासन की महती योजना महतारी वंदन में जो राशि भुगतान कर रहा है वह अकेले परिवहन विभाग ही पूर्ति कर सकता है। यह हम नहीं कहते, विभाग की करारोपण वसूली नीतियां खुद बयान कर रही है। दशकों पुरानी गाड़ियों के नामांतरण में 1.% से लेकर 0.5% का टैक्स समय मानक कर जनता पर भारी पड़ रहा है

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इस के तहत अंतरण कर की वसूली गैर परिवहन यान का 1% और परिवहन यान के लिए 0.5% समय यान के मानक मूल्य की वसूली से परिवहन विभाग मालामाल हो गया है। डेथ गाड़ियों से मतलब है वाहन स्वामी की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारी के नाम पर नामांतरण का अंतरण कर नहीं लेने का फरमान जारी जारी होने के बाद भी वसूली बदस्तूर जारी है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद भी वसूली की जा रही है। क्रय विक्रय नहीं होने और वाहन स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी पत्नी या परिजन से भी वसूली की खबर है। डेथ गाड़ियों का और कृषि वाहनों पर एक परसेंट टैक्स मना करने के आदेश के बाद भी ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 से मालामाल हुआ परिवहन विभाग

- **पांचों उंगली घी में, हाथ जनता की जेब में, यह है सिस्टम की डकैती**
- **आदेश के बाद भी डेथ गाड़ियों और कृषि वाहनों से वसूली जारी**

आदेश ताक पर, वसूली धड़ल्ले से

शासन ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वाहन स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी (पत्नी, पुत्र आदि) के नाम पर ट्रांसफर करने पर कोई अंतरण कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन हकीकत इसके उलट है। रायपुर से लेकर बस्तर तक आरटीओ दफ्तरों में उत्तराधिकारियों से 1% तक टैक्स वसूला जा रहा है।

ऐसे समझें 'वसूली' का यह पूरा खेल

सालाना औसत का गणित: आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रति वाहन औसत वसूली लगभग ₹19,000 से ₹20,000 तक बैठती है। इस लिहाज से विभाग सिर्फ नाम परिवर्तन (Ownership Transfer) के नाम पर सालभर में ₹338 करोड़ से ₹350 करोड़ की औसत वसूली कर रहा है।

मासिक 'उगाही' का आंकड़ा: यदि अधिकतम वसूली के आंकड़ों को देखें (जो कि ₹562.5 करोड़ सालाना है), तो परिवहन विभाग हर महीने जनता की जेब से लगभग ₹46 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल रहा है।

न्यूनतम भी 'भारी': अगर बहुत कम टैक्स का भी आकलन करें, तो भी महीने की औसत वसूली ₹10 करोड़ से कम नहीं है।

आदेश बनाम हकीकत: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ₹338 करोड़ (औसत) की सालाना कमाई में वह हिस्सा भी शामिल है, जिसे सरकार ने 'डेथ केस' और 'कृषि वाहनों' के लिए माफ करने का आदेश दिया था। यानी विभाग अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में अपनों को खो चुके परिवारों और अन्नदाताओं को भी नहीं बख्श रहा है।

राज्यपाल से जारी आदेश

छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

संशोधित आदेश

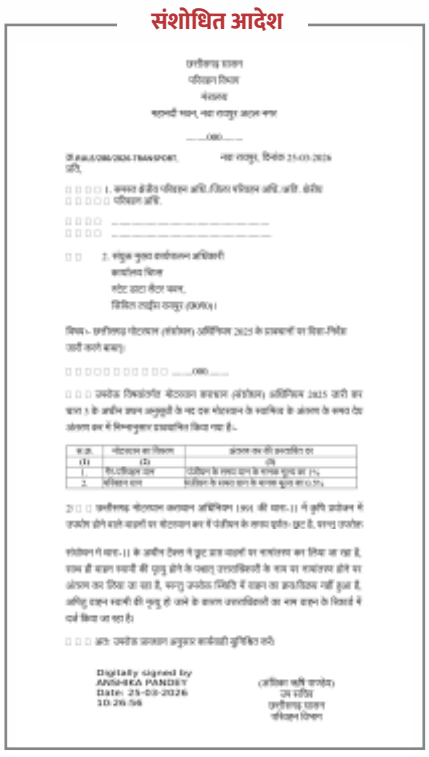
Digitally signed by ANSHIKA PANDEY
Date: 25-03-2026 10:26:56

केस स्टडी (दर्द और दस्तावेज़)

बेवा से भी नहीं बरती रियायत

नाम: सुमित्रा साहू (परिवर्तित नाम), मुंगेली (छ.ग.)
मामला: पति के निधन के बाद घर की एकमात्र पुरानी कार को अपने नाम कराने आरटीओ पहुंचीं।
हकीकत: सुमित्रा को बताया गया कि शासन का आदेश है कि उत्तराधिकारी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब फाइल पोर्टल पर चढ़ी, तो विभाग ने ₹18,000 का डिमांड नोटिस थमा दिया।
अधिकारियों का तर्क: ऊपर से सिस्टम में टैक्स जुड़कर आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। सुमित्रा ने कर्ज लेकर टैक्स पटाया ताकि गाड़ी बिकने से बच जाए।

'वाहन 4.0' बना वसूली का हथियार

बहाना 'सिस्टम' का: परिवहन विभाग के कर्मचारी अक्सर यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि 'वाहन 4.0' पोर्टल में "डेथ केस" या "कृषि वाहन" के लिए जीरो-टैक्स (0% Tax) का विकल्प ही नहीं दिख रहा है।
जानबूझकर देरी?: शासन के आदेश को महीनों बीत गए, लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं करना विभाग की मंशा पर सवाल उठाता है। क्या विभाग जानबूझकर पोर्टल अपडेट नहीं कर रहा ताकि 'टारगेट' पूरा होता रहे?
गलत कैलकुलेशन: पोर्टल 10 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू भी आज के 'बेस प्राइस' पर निकाल रहा है, जिससे

> *"अन्य राज्यों (जैसे एमपी या ओडिशा) में पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर पर एक निश्चित नाममात्र की फीस (Flat Fee) ली जाती है, न कि गाड़ी की वैल्यू का 1%। छत्तीसगढ़ में इसे 'राजस्व' का जरिया बना दिया गया है। 2025 का संशोधन अधिनियम आम आदमी के लिए आर्थिक बोझ है। 'डेथ केस' में टैक्स लेना तो कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत है।"*
> ***अनिल कुमार, परिवहन कानून विशेषज्ञ एवं सलाहकार***

> *विभागीय आदेश और मोटर अधिनियम के विपरित अगर विभागीय कार्य कहीं हो रहा है तो मैं आगामी बैठक में अधिकारियों से जानकारी लेकर निर्देश जारी करूंगा, जनता के पैसों की बेजा वसूली करने वालों को बख्शा नही जाएगा और विभागीय कराधान अधिनियम के तहत ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाएगी।*
> ***केदार कश्यप, परिवहन मंत्री, छग शासन***

साहब की जेब गर्म, जनता की उम्मीदें ठंडी

जवाबदेही किसकी? क्या हो समाधान?

इस पूरी विसंगति के लिए आरटीओ के सॉफ्टवेयर विंग और 'एनफोर्समेंट' के आला अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। शासन के आदेश को पोर्टल पर अपडेट न करना और फील्ड में वसूली जारी रखना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। * ब्लड रिलेशन: पिता-पुत्र, पति-पत्नी या भाई-बहन (रक्त संबंधों) के बीच वाहन ट्रांसफर पूरी तरह निशुल्क होना चाहिए। पुरानी गाड़ियों पर 1% टैक्स 'मानक मूल्य' (Base Price) के बजाय उसकी 'करंट मार्केट वैल्यू' (वर्तमान बाजार मूल्य) पर आधारित होना चाहिए।

अधिनियम की सख्ती, रियायत पर 'ब्रेक'

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 के लागू होते ही विभाग ने वसूली में 'रॉकेट' जैसी रफ्तार पकड़ ली। चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने 'डेथ केस' और कृषि वाहनों के लिए रियायती आदेश तो जारी किए, लेकिन सॉफ्टवेयर और जमीनी स्तर पर इन्हें महिमामंडित (अमल) नहीं किया गया। नतीजा यह है कि आज भी आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और मजबूरन टैक्स भर रहा है।

तिजोरी भरी, पर सुविधा कहाँ?

जब विभाग सिर्फ नाम परिवर्तन से सालाना ₹338 करोड़ से ₹560 करोड़ तक बटोर रहा है, तो यह पैसा कहाँ निवेश हो रहा है? प्रदेश की कई मुख्य सड़कों की हालत जर्जर है, लेकिन भारी-भरकम टैक्स वसूली के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। आधुनिक तकनीक के इस दौर में भी परिवहन विभाग अपनी पुरानी 'डंडा टेक' शैली (लाठी और डर की वसूली) से बाहर नहीं निकल पाया है। हाईटेक सुविधाओं के नाम पर पोर्टल तो बना, पर वह सिर्फ वसूली का जरिया बनकर रह गया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27